सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

02 मार्च, 2021

टर्न-12/आजाद/02.03.2021

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्षः सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे।

वित्तीय कार्य

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, जल संसाधन विभाग की अनुदान की मांग पर वाद विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा।

राष्ट्रीय जनता दल	-	56 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	55 मिनट
जनता दल युनाइटेड	-	33 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-	14 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	-	09 मिनट
ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन	-	04 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	-	03 मिनट
विकासशील इंसान पार्टी	-	03 मिनट
सी0पी0आई0एम0	-	01 मिनट
सी0पी0आई0	-	01 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	-	01 मिनट

माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ....

" जल संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 40,74,38,16,000/-(चालीस अरब चौहत्तर करोड़ अड़तीस लाख सोलह हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।"

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्षः इस मांग पर माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे, श्री राजेश कुमार, श्री अजीत शर्मा, श्री सत्यदेव राम, श्री अखतरूल ईमान, श्री सुधाकर सिंह एवं श्री महबूब आलम से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । ये सभी व्यापक हैं, जिस पर सभी माननीय सदस्य विचार विमर्श

कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे का प्रस्ताव प्रथम है । अतएव माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री विजय शंकर दूबे: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

'' इस शीर्षक की मांग 10/-रूपये से घटायी जाय । ''

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के सिंचाई विभाग की ओर से जल संसाधन विभाग साथ में गिलोटीन में पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग एवं खनन एवं भूतत्व विभाग शामिल है ।

महोदय, जल संसाधन विभाग के मांग पर कटौती प्रस्ताव मैंने इसलिए रखा है कि इसपर व्यापक विचार करने की जरूरत है, इसके औचित्य पर भी विचार करने की जरूरत है । पिछले वर्ष सिंचाई विभाग को जो राशि दी गई थी, यह फरवरी खतम है, मार्च महीना केवल बाकी है, व्यय इस अनुपात में अब वर्ष के अंतिम माह बचे हुए हैं और माननीय मंत्री श्री संजय झा जी को खर्च करने की क्षमता नहीं है, इसीलिए मैं कटौती प्रस्ताव लाया हूँ ।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज दो महत्वपूर्ण प्रंखड है महाराजगंज और भगवानपुर हाट । भगवानपुर हाट 20 पंचायतों का प्रखंड है और 16 पंचायतों का प्रखंड है महाराजगंज । महोदय, इसमें बहुत बड़ा भू-भाग 7000 से लेकर 8000 एकड़ तक भूमि वाटरलॉगिंग की परेशानी से जूझ रहा है वर्षो-वर्ष से महोदय। 1919 में इसका सर्वे हुआ था ......

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : दूबे जी, आवाज क्यों भारी लग रहा है ?

श्री विजय शंकर दूबे : थोड़ा सर्दी हो गया है । आप मेरा ध्यान रखते हैं, धन्यवाद ।

महोदय, 1919 के सर्वे में जल निकासी की व्यवस्था जो अंग्रेजों द्वारा की गई थी, वह बड़ा ही परफेक्ट था । जल निकासी उससे हो जाती थी । सबसे बड़ा बाढ़ का प्रकोप उस इलाके में 1952 में आया था । माननीय जनता का कहना है कि मैं उस इलाके का व्यापक दौरा किया था । वहां के इलाके के लोगों का कहना है कि 1952 में इतनी वाटरलॉगिंग हुई थी, जल निकासी पहले हो गई लेकिन इस बार वाटरलॉगिंग का महोदय जल निकासी अभी तक नहीं हुई । 7000 से 8000 एकड़ जिसमें सवा लाख से लेकर डेढ़ लाख की आबादी किसानों की है, उनके रब्बी के फसल की बोआई आज भी नहीं हो पायी है । राज्य के माननीय मुख्यमंत्री 2019 में वहां दौरा किये थे । जल निकासी का आलम यह है कि महाराजगंज, बनियापुर और मशरख, तरैया यह सारे इलाके इससे प्रभावित होते थे और उसी के जंक्शन पर माननीय मुख्यमंत्री का हेलीकोप्टर उतरा था । जल जमाव को देखकर के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम मछली पालन का हब बनायेंगे। लोगों ने पूछा कि कब बनायेंगे, तिथि एकचुअल नहीं

दिया, उन्होंने कहा कि जल्दी बनायेंगे, ये लोगों का बताना था, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर गये थे । इतनी बातें कहे हैं, वह रेकोर्ड पर है । लेकिन महोदय आज तक वहां कोई काम नहीं हुआ । इसीलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूँ कि उस इलाके का आप व्यापक दौरा करें । आखिर राज्य के डेढ़ लाख किसानों को ऐसे ही रोते-बिलखते नहीं छोड़ा जा सकता और इसका दौरा करके जल निकासी की योजना बनायें । जल की निकासी हो, वहां पर बड़ी उपजाऊ भूमि है लेकिन एक फसल पैदा होता है । इसीलिए मैं मांग करता हूँ माननीय मंत्री से कि जब भी फुर्सत हो, आप इरीगेशन के अधिकारी-पदाधिकारियों को समय देकर के और उसके पहले वो तीनों चॅवर जो हैं, प्रमुख तीन चॅवर हैं । महोदय, 20 पंचायत इसमें इनवॉल्व है जिसमें 12 पंचायतों महम्मदपुर, सोंधानी, बनसोही खेड़वा, महम्मदा, सराय पड़ोली, बिठुना, मोरा खास, शंकरपुर, बलहा एराजी, मिरजुमला और गोपालपुर प्रमुख हैं । इन सारे इलाके में माननीय मंत्री जी दौरा करें, यह सब ऑनरोड है, एन0एच0 पर है । इन इलाकों का दौरा करके माननीय मंत्री जी योजना बनायें, यह मैं आपके माध्यम से महोदय सरकार से यह मांग करता हूँ । महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि मुझे ज्यादा बोलने के लिए डॉक्टर ने मना किया है लेकिन ......

अध्यक्ष : इसलिए अब संक्षिप्त कर लें ।

श्री विजय शंकर दूबे : नहीं महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि यह मैंने लिखित भी तैयार कर दिया है । वह मैं सदन पटल पर रख देता हूँ वो प्रोसिडिंग्स का पार्ट कृपया बनवा दें ।

अध्यक्ष : जो विषय आप बोल चुके हैं, वह रख देंगे ।

श्री विजय शंकर दूबे : इस विषय पर महोदय ....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, अभी तो हमारी बात खतम नहीं हुई, एक-दो मिनट और ।

अध्यक्ष : आपका समय फिर आगे के वक्ता से कटेगा । सात मिनट का समय हो गया ।

श्री विजय शंकर दूबे : दो मिनट महोदय । इसमें ....

अध्यक्ष : ठीक है, अब अगला वक्ता से कट जायेगा ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, इसमें सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग शामिल है, इसीलिए महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन चल रहा है इनटायर ऑपोजिशन और ऑपोजिशन के माननीय सदस्यों का, रूलिंग पार्टी के माननीय सदस्यों का छपने का अधिकार है । केवल सरकार को ही छपने का अधिकार नहीं है, वो अधिकार हमें भी प्राप्त है । इनको भी प्राप्त है । कल राज्य के कृषि प्रधान प्रदेश में एग्रीकल्चर का डिमांड था, एग्रीकल्चर पर डिवेट हुए

..... क्रमशः .....

टर्न-13/शंभु/02.03.21

श्री विजय शंकर दूबे : क्रमश: महोदय, कट मोशन मेरा था आसन से नाम पुकारा गया और आसन के परमिशन से मैंने निवेदन किया । अखबार में यहां तक महोदय, आश्चर्य तब है कि इस राज्य का लीडिंग अखबार, अखबारों के नेता हिन्दुस्तान में नाम तक नहीं लिया गया कि कट मोशन आया कि नहीं आया राज्य सरकार ऐसे ही प्रस्ताव खारिज कर ली यह दुखद विषय है । इसीलिए महोदय, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है । ये मैं निवेदन करता हूँ किसी भी पत्रकार को उनकी भावना को आहत करने का मेरा उद्‌देश्य नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य चाहे इधर के हों या उधर के हों उनको छपने का बराबर संवैधानिक अधिकार है ।

अध्यक्ष : अब समाप्त करें, बैठ जाएं ।

श्री विजय शंकर दूबे : इसलिए महोदय, आपको आसन को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

अध्यक्ष : श्री सुधाकर सिंह ।

श्री सुधाकर सिंह : महोदय, पहली बार बिहार विधान सभा में चुनकर मैं आया हूँ रामगढ़ से, आपने मुझे समय दिया इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ और जिन लोगों ने चुनकर मुझे भेजा उनको धन्यवाद देता हूँ । जल संसाधन विभाग के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में आज खड़ा हूँ । मैं जनरल बजट विस्तार से देख रहा था 2019-20 जो सत्र बीता है उसमें सिंचाई परियोजनाओं के सृजन के लिए 380 करोड़ मात्र खर्च हुआ । मुझे आश्चर्य हुआ कि 380 करोड़ से ज्यादा हुआ होगा, आप इसको देखवा लें, चूंकि आप मांग रहे हैं 4 हजार करोड़ ।

अध्यक्ष : माइक पर बोलिये ।

श्री सुधाकर सिंह : जी । आप इस बात को देखवा लें दुबारा कि 4 हजार करोड़......

अध्यक्ष : इसको निकालेंगे तो और फ्री होकर बोलेंगे ।

श्री सुधाकर सिंह : महोदय, 4 हजार करोड़ रूपये आप मांग रहे हैं इस साल खर्च के लिए और 2019-20 में मात्र बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर 380 करोड़ रूपये खर्च करते हैं । आप 2020-21 में 1724 करोड़ बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए मांगा था बजट में, आपके विभाग के द्वारा आश्चर्यजनक रूप से 456 करोड़ रूपये और अतिरिक्त मांगा गया, आपका बजट 2180 करोड़ रूपया सिंचाई पर- मैं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं को छोड़कर बात करता हूँ । इस साल जब 2180 करोड़ रूपये खर्च करने की आपकी क्षमता है । बिहार का बजट घटा नहीं है फिर भी इस साल आप मात्र 1740 करोड़ रूपये सिंचाई परियोजनाओं के लिए मांगा है । यह तीन सालों का आपका जो अंतर है कहीं न

कहीं विभाग के स्तर पर योजनाओं के चयन में जो प्राथमिकताएं होनी चाहिए वह ठीक से उसमें समेकित रूप से विभाग प्रयास नहीं कर रहा है । मैं इस मामले में कहना चाहता हूँ कि सिंचाई विभाग कृषि रोड मैप के जरिए चूंकि कृषि रोड मैप जो बना था द्वितीय 2012-17 और अभी जो हमारा तृतीय कृषि रोड मैप चल रहा है 2017-22 इसमें कृषि विभाग का इसमें सिंचाई विभाग का लक्ष्य रखा गया था कि हम साढ़े 11 लाख हे0 पूरे बिहार में नये सिंचाई सृजन की क्षमता का निर्माण करेंगे और जो बजट आपने मांगा इस सदन के माध्यम से उसको बजट ही उपलब्ध कराया गया कई विभाग को लेकिन आश्चर्यजनक है कि जो द्वितीय कृषि रोड मैप 2012-17 समाप्त हुआ 11 लाख 56 हजार हे0 के मुकाबले मात्र 77 हजार हे0 का आप नया सृजन करते हैं, अगर प्रतिशत के रूप में देखा जाय तो साढ़े 6 फीसदी उपलब्धि आपकी रही है । आज भी कोई परीक्षा में बैठता है तो 40-45 परसेंट से नीचे तो उसको पास मार्क्स मिलता नहीं है तो साढ़े 6 परसेंट उपलब्धि पर आपकी सरकार को कैसे हमलोग पास करें यह तो विधान सभा के विवेक पर है । इतना ही नहीं जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जब छात्र राजनीति से निकलकर के चुनावी राजनीति में शामिल हो रहे थे, करीब 45 साल एक लंबा वक्त होता है । उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा 1975 के आसपास मोकामा टाल-मोकामा बड़हिया टाल जिसको बोलते हैं । मोकामा बड़हिया टाल की समस्या को समाप्त करने की राजनीति करते हुए विधान सभा, लोक सभा, केन्द्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, विधान परिषद् तमाम पदों को सुशोभित किया । मोकामा टाल समस्या उनके व्यक्तित्व को इतना बड़ा टौल बनाया, इतना बड़ा उनके व्यक्तित्व का निर्माण किया, लेकिन जो मोकामा टाल की समस्या है आज भी उतना ही टौल वह समस्या बनी हुई है । 1972 में 1 लाख 6 हजर हे0 डूब का क्षेत्र है जिसमें नालन्दा, पटना, शेखपुरा, नवादा पांच जो जिला हमारा फैला हुआ बाढ़ बड़हिया का जिसको टाल कहते हैं । लंबे प्रयास के बाद भी इतना बड़ा पद मुख्यमंत्री जी को मिला, सरकार 15 साल से चला रहे हैं । इससे पहले भी वे केन्द्र में कृषि मंत्री के रूप में रहे, लेकिन 1 हजार हे0 भी जल जमाव से मुक्त नहीं हुआ इससे बड़ा आश्चर्य नहीं हो सकता । बीच-बीच में चर्चा होती है कि 4600 करोड़ रूपये से हमलोग बाढ़ बड़हिया टाल की समस्या को समाप्त करेंगे । फिर उसमें पुनरीक्षित कोई बात होती है कि उसमें 1900 करोड़ रूपये लगेंगे । मुझे याद है कि लोक सभा चुनाव के पूर्व, 2019 का जो लोक सभा चुनाव था तो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी सभा हुई थी उस इलाके मोकामा में जिसमें नितिन गडकरी जी तत्कालीन जल संसाधन मंत्री भी थे, पार्टी के कार्यकर्त्ताओं के कहने पर चर्चा किया था कि यह कौन सी ऐसी समस्या है जो सुलझ नहीं रही है । उस समय के तत्कालीन मंत्री ने कहा था कि डी0पी0आर0 बनवाकर भेजे बिहार सरकार इस समस्या को दूर करने का मैं काम

करूँगा । पिछले दो साल बीत गये डी0पी0आर0 कहां है यह किसी को पता नहीं है । लेकिन वह बाढ़ बड़हिया टाल के इलाके का विस्तार हुआ है । मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ इसकी जॉच करा ली जाय । मोर, कन्हाइपुर, सुल्तानपुर टाल, मरांची, औंटा टाल, चिंतामणिचक ये प्रखंड मोकामा और घोसवरी का जो इलाका है वहां नये जल जमाव पैदा हुए हैं । हमको तो आशा थी कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में टाल की समस्या समाप्त होगी । राजनीति में उनको जहां जाना चाहिए शायद सर्वोच्च स्तर पर हैं, प्रधानमंत्री बनें हमारी इच्छा है, बिहार का विकास होगा, लेकिन वह समय बतायेगा । इन तमाम सवालों को लेकर के जब हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं तो आपने क्या प्रावधान किया है उस समस्या के समाधान के लिए हमलोगों को पता नहीं है क्योंकि जो उपलब्धि है वह शून्य है । अगर मान लीजिए पैसे आपको चाहिए तो पैसे की कोई कमी नहीं है जैसा सरकार कह रही है, 2 लाख करोड़ का बहुत बड़ा बजट होता है । 1 लाख 6 हजार हे0 का जल जमाव कोई बड़ी समस्या नहीं है उसके लिए क्या सरकारों ने प्रयास किया यह मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब लालू प्रसाद जी की सरकार थी तो उस योजना की समस्या के समाधान के लिए गंगा में कई जगह कट प्वाइंट बनाये गये थे, लेकिन कट प्वाइंट जो बने उसका जो विस्तार होना चाहिए था वह बाद के कालखंडों में केवल कागजी ही साबित हुआ । सिंचाई विभाग की जल प्रबंधन का जो सवाल है उसपर हमारी पार्टी के सदस्य बोलेंगे । मैं मुख्यत: जो सिंचाई परियोजनाओं पर है उसपर ही फोकस करना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यह जो सरकार है यह जो 16 सालों से किसी एक योजना का नाम बताने का काम करे जो वर्तमान सरकार ने शुरू किया हो और सौ फीसदी पूरी हो गयी हो, कोई एक योजना ।

क्रमश:

टर्न-14/ज्योति/02-03-21

क्रमश:

श्री सुधाकर सिंह : यहॉ तक कि पहले से पूर्व से जो योजनाएं चल रही है, कोई एक योजना का नाम जो पहले से चल रही हों उसको सौ फी सदी सरकार ने पूरा करने का काम किया हो । मैं पिछली बार का बजट भाषण पढ़ रहा था, 15 साल बनाम 15 साल की बात की चर्चा थी, उस चर्चा में उपलब्धियों की चर्चा नहीं थी । खर्चे की चर्चा थी कि तब 34 सौ करोड़ रुपया 15 सालों में खर्च हुआ और हमारी सरकार ने 15 सालों में 22 हजार करोड़ रुपये खर्च की । यह सुनने में अच्छा लगा लेकिन किसी बजट का जो पेश होता है तो उस बजट का तीन हिस्सा होता है जेनरल बजट और दूसरा होता है जेंडर बजट और तीसरा होता है रिजल्ट बजट । अब इसमे जेंडर बजट की इसलिए मैं

चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सिंचाई एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसानों के खेत का पटवन होता है इसलिए स्त्री-पुरुष का बंटवारा इसमें महत्व नहीं रखता है क्योंकि दोनों ही समान रुप से लाभान्वित होते हैं । लेकिन जब हम परिणाम बजट की बात करते हैं तो 1990 से पहले इस बिहार में कितना पटवन होता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा को देखा और जब हमलोगों ने पढ़ा तो यहॉ सिंचाई विभाग का मुख्य काम सिंचाई की क्षमता का सृजन था । बजट इसीलिए इशु होता था लेकिन उससे पटवन कितना हुआ इसपर कभी चर्चा नहीं होती थी इसीलिए उस सरकार ने तय किया था 15 साल की सरकार जो राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद की सरकार थी, उन्होंने तय किया कि हम जो पैसा लगायेंगे उसका हमको परिणाम चाहिए और जब आकलन हुआ तो उस समय काल्पनिक सवाल 30 लाख, 27 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ और तत्कालीन सरकार ने अध्ययन किया तो 12 लाख हेक्टेयर का पटवन होता था वास्तविक रुप से तो इसको बोलते हैं हमलोग वाटर डिपोजिट तो हम जब वाटर डिपोजिट से जब लेते हैं पानी, हम जो रेगुलर जहॉ से डिस्चार्ज होता है जिस प्वायंट से हम जो पानी डिस्चार्ज करते हैं और टेल एंड तक न पानी पहुंचे तो उस पानी को हमलोग पटवन नहीं मानते और मानना भी नहीं चाहिए और उसका सही आकलन कैसे है ? आप जब पानी का कहते हैं कि हमने इतना क्यूसेक पानी खेतों की तरफ भेजा और खेतों में नहीं पहुंचा उसका आकलन करने का विभाग के पास एक ही मिकैनिज्म है कि कितना रेवेन्यू कलेक्शंस हुआ तो जब रेवेन्यू कलेक्शंस के लिए अमीन जाता है खेतों पर और देखता है कि कितना पटवन हुआ तो उसी को वास्तविक आकलन का आधार सिंचाई विभाग मानता रहा पिछले 15 सालों में तब 12 लाख हेक्टेयर से जब सरकार ने प्रयास किया तो कम संसाधनों में 18 लाख हेक्टेयर तक पटवन सुनिश्चित करने का काम किया था और आज जब हम देखते हैं परिणाम बजट की तरफ तो आज परिणाम बजट पेश नहीं हुआ है लेकिन जब आपके जो भाषण है पिछले साल का उसको जब मैं देखता हूँ तो बिहार में वास्तविक रुप से पटवन जिसको आप स्वीकार करते हैं मात्र 19 लाख हेक्टेयर तो 16 साल में मात्र एक लाख हेक्टेयर जिसको मैं नहीं मानता क्योंकि जो अभी की सरकार है वर्तमान सरकार वह कभी भी अध्ययन करने का प्रयास नहीं किया कि हमको रेवेन्यू कितना आया ? कितना लाख हेक्टेयर का रेवेन्यू राज्य सरकार के खजाने में जमा हुआ । बहुत छोटी रकम होती है सरकार के लिए और वह बहुत महत्व नहीं रखता । करीब 25-30 करोड़ की छोटी रकम होती है, वह सरकार के लिए बड़ी रकम नहीं है किसानों के लिए भी कोई बड़ी रकम नहीं है लेकिन जब जाता है सरकार का पदाधिकारी और कर्मचारी और किसान से संवाद करता है तब पता चलता है कि वह पानी छोड़ा था 1 लाख हेक्टेयर के लिए

और पटवन हुआ कितना ? 60 हजार हेक्टेयर यही उसका माप करने का तरीका होता है तो जो 19 लाख हेक्टेयर पर राज्य सरकार का जल संसाधन विभाग कह रहा है कि मेरा पटवन तो आखिर 22 हजार करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती । 22 हजार करोड़ रकम खर्च करने के बाद बिहार में मात्र 1 लाख हेक्टेयर नये पटवन की व्यवस्था हुई है इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता । सिंचाई के लिए पूरे बिहार में तीन हमलोग मानते हैं बड़ी बेसीन योजना जिसको हम लोग बोलते हैं नदी बेसीन योजना जो एक हमारा कोशी नदी बेसीन योजना है, दूसरा गण्डक बेसीन योजना है तीसरा सोन बेसीन योजना है । पानी तो सबसे ज्यादा गंगा में है जरूर लेकिन हमलोगों ने गंगा का पानी का इस्तेमाल आज तक बिहार के भीतर नहीं कर पाए एक लंबी कहानी है लेकिन मैं आता हूँ आपके सोन प्रणाली पर जो पूरे बिहार में जो सिंचाई का पटवन है तकरीबन 40 प्रतिशत जो पटवन जो सुनिश्चित होता है वह सोन नहर प्रणाली से होता है बिहार का करीब 7 लाख हेक्टेयर के आस पास और बिहार के खाद्यान्न के जो उत्पादन हैं जो बिहार को हंगर स्टेट जो ग्लोबल हंगर इण्डेक्स है उसमें बिहार को इज्जत बचाने वाला जो एरिया है वह हमारी सोन की नहर प्रणाली जिसमें 40 प्रतिशत पूरे बिहार में जो पटवन होता है अकेले 40 प्रतिशत पटवन करती है और खाद्यान्न जो पैदा होता है बिहार के भीतर वह करीब 50 परसेंट खाद्यान्न का योगदान करता है अकेले जो सोन का जो इलाका है लेकिन जब उसमें बजट की बात करते हैं तो सबसे कम बजट का प्रावधान है । मैं बताना चाहता हूँ यह जो सोन नहर प्रणाली को बचाने में राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ी महती भूमिका का इस्तेमाल किया था जब वाणसागर समझौता हो रहा था, इस देश के भीतर कई अन्तर्राज्यीय समझौते थे उस समझौते में बिहार के साथ नाइंसाफी हुआ था फिर भी उस नाइंसाफी के विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन 7.7 लाख एकड़ फीट पानी हमको समझौते में मिला जिसमें हमको वाणसागर से 7.5 लाख एकड़ पानी और .2 लाख एकड़ पानी हमको गंगा से मिलना था जिसको उत्तर प्रदेश से उठाना था हमको वह आज तक .2 लाख एकड़ फीट का तो हिसाब छोड़ दीजिये । उस समय गुरवत में बिहार की सरकार थी , संसाधनों की कमी थी । केवल बिहार के साथ ही नहीं उस समय उत्तर भारत के जितने राज्य थे उस समय आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे । आर्थिक उदारीकरण का दौर 92 के पास, राज्य सरकारों के पास पैसे की आमदनी बढ़ी थी उस दौर में भारत सरकार ने ..

अध्यक्ष : संक्षिप्त कर लीजिये ।

श्री सुधाकर सिंह : कुछ समय दिया जाय पार्टी सहमत है कुछ बढ़ा दिया जाय पार्टी अपना समय कम कर लेगी । उसमें बिहार सरकार ने ...

अध्यक्ष : जितना समय पार्टी दिया है वह पूर्ण होने जा रहा है ।

श्री सुधाकर सिंह : वह बढ़ा दिया जाय सर ।

अध्यक्ष : किनका समय कम किया जाय ?

श्री सुधाकर सिंह : वाणसागर परियोजना को, बिहार सरकार गुरवत में भी, एक मुश्त रकम देकर वाणसागर को बनवाने का प्रयास किया जिसका परिणाम है कि सोन नहर प्रणाली आज भी 80 से 90 फीसदी पर आज भी काम करने में कामयाब है और बिहार के टोट्ल सिंचाई का करीब करीब 40 प्रतिशत वह पटवन करती है आज उसी सोन का आधुनिकीकरण हुआ था उसी जमाने में और सोन का आधुनिकीकरण- यह सोन नहर कोई आसानी से नहीं मिला । वह 1857 का जो सिपाही विद्रोह था, वीर कुवॅर सिंह के नेतृत्व में बड़ी लड़ाई लड़ी गयी थी तो अंग्रेजों द्वारा अध्ययन हुआ कि इस इलाके के लोग बहुत मेहनती है लेकिन बंजर जमीन के चलते ये लोग बड़े लड़ाके प्रवृति के हैं इसीलिए उस समय के अंग्रेजों की सरकार ने इस परियोजना को देने का काम किया था और वह मुख्यत: बनी थी रबी फसल के लिए बाद में जब राष्ट्रीय जनता दल 1990 में, 100 साल के बाद जबकि वह रबी की फसल के लिए पटवन के लिए यूज होता था लेकिन 1990 में जब सरकार बनी तो सोन संघर्ष समिति के आन्दोलन का प्रभाव था कि उसको खरीफ पटवन के लिए भी उस नहर प्रणाली को उसकी क्षमता को, पूरा करने का प्रयास सरकार ने किया और इसके लिए बड़ी रकम उन्होंने दिया था लेकिन उसमं से एक छोटा सा काम 2004 में रह गया था । उसमें पैरेलल कैनाल बनाना था डिहरी में जिससे कि पानी की क्षमता को दोगुना ज्यादा किया जा सके लेकिन यह एन.डी.ए. की सरकार 12 साल तक कान में तेल डालकर सोयी रही । 12 साल के बाद मात्र 5 प्रतिशत सोन आधुनिकीकरण का काम जो था उसको देर से करने का काम हुआ । परिणाम क्या हुआ कि जो हमारी जो हमारी कैनाल सिस्टम है पूरा सोन का वह जर्जर स्थिति में पहुंच गयी जो आधुनिकीकरण हुआ था स्वाभाविक है मिट्टी का क्षरण होता है । कोई भी आप रिमौडलिंग करते हैं तो उसका 15 से 20 साल से ज्यादा लाईफ नहीं होता । उस इलाके में फिर भी आज भी मैं धन्यवाद देना चाहता हॅू। इस सरकार को देर से ही सही लेकिन वह जागी लेकिन आज भी वह पैरेलल चैनल हन्ड्रेड परसेंट कंपलीट नहीं हुआ । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि थोड़ा सा जो भी पैसा लगे उसको पूरा कराने का काम करेंगे। सोन बेसिन का एक पार्ट है कर्मनाशा नहर प्रणाली जो मेरे इलाके से गुजरती है उसपर दो पुराने पम्प हाउस लगाए गए थे, 1998 में लरमा पंप और 2004 में विश्वकर्मा पंप लेकिन कोई भी जो तकनीकी विशेषज्ञ जानते हैं कि किसी भी पम्प का मोटर का लाईफ 10 साल से 12 साल से ज्यादा नहीं है लेकिन पम्प हाउस 22-23 साल पुराने हो चुके हैं

और अगर सरकार उसको पुनः मेंटेन करने के लिए नये मोटर को इंसटौल नहीं करेगी तो वह परियोजना फिर डेथ कर जायेगी । हमारे बिहार में यही सबसे बड़ी चुनौती है हम तो योजना तो बनाते हैं लेकिन कोई मेंटीनेंस पॉलिसी नहीं होने के कारण वह कभी भी उच्चतम क्षमता पर काम नहीं करती । इसके लिए विशेष उपाय करने होंगे । मैं देख रहा हूँ कि इसमें 150 करोड़ रुपये केवल इसमें खर्च कर रहे हैं मेंटीनेंस पर जो हमारी पुरानी परियोजनाएं हैं यह 150 करोड़ बहुत ही कम हैं । आप नयी योजनाओं पर पैसे लगातार बढ़ा रहे हैं हम तो सरकार को सलाह देंगे नयी परियोजना पर कम व्यय कीजिये पुरानी जो परियोजनाएं हैं उसको मेंटेन करने का काम करेंगे ।

क्रमशः

टर्न-15/पुलकित/अभिनीत/02.03.2021

श्री सुधाकर सिंह (क्रमशः): इसी क्रम में हम बताना चाहते हैं, दूसरी बड़ी परियोजना है गंडक परियोजना जिसमें दो कैनाल हैं तिरहुत और सारण । तिरहुत कैनाल का जो सिस्टम था, जब बना था उसके हिसाब से उसको मुजफ्फरपुर से बढ़कर वैशाली तक आना था लेकिन आजतक कोई परियोजना मुजफ्फरपुर से आगे नहीं बढ़ सकी है । 16 साल से डबल इंजन की सरकार है, हमलोगों को लगा था कि जरूर आगे बढ़ेगी । गंडक परियोजना का निर्माण 8 लाख हेक्टेयर तक के लिए हुआ था और अधिकतम चार, साढ़े चार लाख हेक्टयर तक उससे पटवन हुआ है । आज वास्तविक रूप से देखते हैं तो दो लाख हेक्टयर से कम पटवन, हमलोग कई सालों से देख रहे हैं । इसका कारण यह है कि इसकी प्रोपर मरम्मति जो होनी चाहिये उस मरम्मती का प्रावधान नहीं किया जा रहा है । हमारा कोसी जो बेसिन है, जो 1985 की बाढ़ में ध्वस्त हो गया था, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार जब 1990 में आई चार साल, 1994 तक उसको पुनर्स्थापित करने का काम किया और उस परियोजना से चार लाख हेक्टेयर तक पटवन करने का काम हुआ था ।

आज जब बाढ़, हमारे आदरणीय विद्वान मंत्री बैठे हुए हैं, 2007 में जो कुसहा का तटबंध टूटा वह सब जानते हैं, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ । 2007 के बाद से 2 लाख हेक्टेयर से भी कम पटवन रह गया है जो कभी 4 लाख हेक्टेयर पटवन करता था । बिहार सरकार ने इसमें काफी पैसा भी लगाया लेकिन आज तक योजना, आज भी चार लाख, जो पुरानी क्षमता होनी चाहिये थी आठ लाख वह नहीं हुई । वेस्टर्न कैनाल पर बनने वाला जो हमारा साइफन था वह आजतक नहीं बन पाया है जिसके कारण इसका अधिकतम उपयोग हमलोग नहीं कर पा रहे हैं । गंगा का जो सवाल है हमारे सामने, किसी जमाने में भारत की सरकार और देश के लोगों ने माना था कि बिहार सरप्लस वाटर एरिया है, वह एक काल्पनिक सवाल था, एक काल्पनिक आकलन था,

जिसके आधार पर बिहार सरकार ने बहुत लड़ा कि हमारे पास कोई सरप्लस नहीं है । एक जमाने में आया कि गंगा और कावेरी का हमारा लिंक बनेगा और वह गंगा-कावेरी का लिंक हरिद्वार से कावेरी नहीं जुड़ेगी, वह लिंक पटना से कावेरी बनेगा जिसका बिहार सरकार ने विरोध किया और इस योजना को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया था तब बिहार सरकार, तत्कालीन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ने द्वितीय सिंचाई आयोग बनाने का काम किया था कि बिहार के पास सरप्लस वाटर है या डेफिसिट स्टेट है और उस आकलन के आधार पर 8 वॉल्यूम में एक मोटी किताब और उस द्वितीय सिंचाई आयोग के सदस्य थे हमारे आदरणीय वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जिनके हस्ताक्षर से 8 वाल्युम की जो किताब है वह देश ही नहीं दुनिया के लिए वह मानक रिपोर्ट है । इसमें पता चला कि पानी के मामले में हम डेफिसिट स्टेट हैं, हम सरप्लस स्टेट नहीं हैं । उसी काल में सरकारों ने तय किया कि हम पानी की एक बूंद भी बिहार से दूसरे राज्य को देने का काम नहीं करेंगे लेकिन हम गंगा से पानी उठाने में नाकामयाब रहें । एक चौसा में छोटा पम्प है और एक भागलपुर में बटेश्वर पंप योजना है, जिसको आपके द्वारा शुरू करते ही टूट गया था, आप जानते ही हैं लेकिन केवल मैं कह रहा हूँ कि गंगा का डिसिल्टेशन कर दें । किसी जमाने में डच कारोबारी, ब्रिटिश कारोबारी इसी गंगा के माध्यम से नौ परिवहन के जरिए बिहार में अपना कारोबार करते थे । पानी का उपयोग केवल खेतों में सिंचाई के लिए नहीं होता, जब कि पानी के कई उपयोग हैं, पीने से लेकर के, जानवरों के पीने से लेकर के, इंसानों के पीने से लेकर के, खेतीबाड़ी से लेकर के नौ परिवहन तक है । गंगा का अगर आप डिसिल्टेशन करते हैं और कोसी का डिसिल्टेशन करते हैं...

अध्यक्ष: अब समाप्त करें ।

श्री सुधाकर सिंह: महोदय, बस दो मिनट में समाप्त करता हूँ ।

अध्यक्ष: वह दो मिनट भी आपका घटेगा ।

श्री सुधाकर सिंह: केवल इतना ही नहीं मैंने जो कहा था, चर्चा की थी कि सरकार कोई एक योजना बता दे, किसी पुरानी योजना को शत-प्रतिशत पूरा कर दिया हो तो मंत्रीजी अपने जवाब में जरूर इसका उल्लेख करेंगे । उत्तरी कोयल की जो हमारी परियोजना है, जिस पर आजतक गेट नहीं लगा है । प्रधानमंत्रीजी ने चुनाव के दौरान वहां जाकर आश्वासन दिया था कि हम इस परियोजना को चालू करेंगे । मुहम्मदगंज में जो बैराज है नीचे, जिससे वहां अधिकतम पटवन होता है, इसका हम इसलिए उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे उत्तरी कोयल में बना हुआ जो डैम है उसमें केवल गेट लगाना है जो आजतक नहीं लग पाया है । एक साधारण बात है, दुर्गावती जलाश्य परियोजना जो केवल 5 प्रतिशत काम के लिए रूकी हुई थी, वह इस एन0डी0ए0 की सरकार में जिसे 16 साल हो गये,

आज भी 5 प्रतिशत जो काम बचा हुआ था आज तक पूरा नहीं हुआ है । इसका परिणाम यह निकला कि उस इलाके की जो नहरें हैं, जो परियोजना पूरी होने से पहले ही टूट गई है, कई ऐसे सवाल हैं, समय हमारी पार्टी की तरफ से जो निर्धारित था, हम इतना ही उपयोग कर पाये, फिर भविष्य में कभी अवसर मिला तो अपनी बात को रखेंगे । धन्यवाद ।

अध्यक्ष: श्री विद्या सागर केशरी, आपका 8 मिनट का समय है ।

श्री विद्या सागर केशरी: महोदय, आज जल संसाधन विभाग के द्वारा लाये गये अनुदान मांग, जिसकी राशि 40,74,38,16,000/- (चालीस अरब चौहत्तर करोड़ अड़तीस लाख सोलह हजार) रूपये हैं, इसके पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ । अध्यक्ष महोदय, आपने जो बोलने का मुझे अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, साथ ही मैं अपने इस प्रदेश के मुखिया और इस राज्य के उप मुख्यमंत्री जिनके कुशल वित्तीय प्रबंधन के द्वारा आज जो बजट लाया गया है, वह बहुत ही सराहनीय बजट आज सदन के समक्ष पेश किया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्व में महासागर पृथ्वी को लगभग तीन-चौथाई भाग से घेरे हुए हैं । संयुक्त राष्ट्र के आकलन के मुताबिक पृथ्वी पर पानी की कुल मात्रा लगभग 1400 मिलियन घन किलोमीटर है जिससे पृथ्वी पर पानी की तीन हजार मीटर मोटी परत बिछ सकती है । अध्यक्ष महोदय, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी में से मीठा जल लगभग 2.7 प्रतिशत है, जबकि इसमें लगभग 75.2 प्रतिशत जल ध्रुवीय प्रदेशों में हिम के रूप में विद्यमान है तथा 22.6 प्रतिशत जल भू जल के रूप में विद्यमान है । शेष जल झीलों, नदियों, वायुमंडल, नमी, मृदा और वनस्पति में मौजूद है । अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन की महत्ता तब और बढ़ जाती है, जल की महत्ता तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसके बारे में मैं एक पंक्ति सुनाकर के आपको बताना चाहूंगा कि-

''भुवन-भास्कर क्रोध में उगले धूप की आग,
दिन सन्नाटे से सना, रात फुसकती नाग,
जल-जीवन अनमोल है, सृष्टि का परिधान,
अमृतमय हर बूंद है, श्रेष्ठ प्रकृति वरदान ।''

अध्यक्ष महोदय, इस धरा पर उपयोग और अन्य इस्तेमाल के लिए प्रभावी रूप से उपलब्ध जल की मात्रा बहुत थोड़ी है, जो नदियों, झीलों और भू-जल के रूप में उपलब्ध है । अधिकांश जल इस्तेमाल के रूप में उपलब्ध न होने और इसकी उपलब्धता में विषमता होने के कारण जल संसाधन विकास और प्रबंधन की आवश्यकता को समझते हुए जल के महत्व को पहचाना गया और इसके उपर्युक्त प्रयोग तथा बेहतर प्रबंधन पर अधिक जोर दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, राज्य में जल की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है, इसके बावजूद बाढ़ की समस्या खड़ी है । हमलोगों के सामने में, सिंचाई के लिए समय

से खेत पर पानी नहीं मिल पाता है । इन सभी समस्याओं के निदान के लिए राज्य सरकार ने महती महत्वाकांक्षी योजनाएं लाकर के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए एक अच्छा कदम उठाया है । अध्यक्ष महोदय, बाढ़ की समस्याओं से निदान के लिए हमारे ही पूर्णिया प्रमंडल में महानंदा बाढ़ प्रबंधन योजना फेज-2 के तहत...

(क्रमशः)

टर्न-16/हेमन्त-धिरेन्द्र/02.03.2021

....क्रमशः....

श्री विद्यासागर केशरी : राज्य सरकार ने सात अरब बयानवे करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी है, जो कोसी क्षेत्र के लोगों के लिए, खासकर इन चार जिलों अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, इन चारों जिलों के लिए एक वरदान साबित हुई है । अध्यक्ष महोदय, जब कुशा की बाढ़ आयी थी और कुशा का बांध टूटा था, उस समय की जो त्रासदी थी, उस त्रासदी का अगर ख्याल किया जाय तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र थे ये ही चार जिले थे । उन प्रभावित जिलों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाकर उस क्षेत्र की जनता के लिए एक वरदान के रूप में महानंदा बाढ़ प्रबंधन योजना का कार्यक्रम दिया है, यह क्षेत्र के लिए वरदान साबित हुआ है । अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में जलांतरण के लिए भी कई एक महत्वाकांक्षी योजनाएं बनायी गयी हैं, जिसमें नदियों को जोड़ने की योजना के तहत कोसी बेसिन से महानंदा बेसिन में जलांतरण की एक महत्वाकांक्षी योजना 'कोसी मेची लिंक योजना' पर भारत सरकार का इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस दिनांक- 08.12.2020 को प्राप्त कर लिया गया है । इसे राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल करने पर सहमति प्रदान कर ली गयी है ।

(इस अवसर पर माननीय सभापति श्री अवध विहारी चौधरी ने आसन ग्रहण किया)

सभापति महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर जी के बजटीय नेतृत्व के तहत और उनके भाषण की कई योजनाओं का, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है, जिन्हें 2021-22 के वित्तीय वर्ष में सम्पन्न किया जाना है । उन सभी योजनाओं में यथा गया के विष्णुपाद मंदिर के सामने फलगू नदी में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित हेतु 266 करोड़ की योजना, जिसे 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है, जिसे आई0आई0टी0, रुड़की के इंजीनियर लोग संपादित कर रहे हैं । सभापति महोदय, बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना के तहत 548.13 करोड़ रु0 से तटबंध निर्माण हेतु प्राप्त स्वीकृति के आलोक में 2021-22 में कार्य प्रारंभ किया गया है । इसी संदर्भ में हमारे यहां जो क्षेत्रीय कुछ बाते हैं, उसके

संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा, चूंकि समय बहुत कम है । एक हमारे यहां हिमालय से कजरा नदी निकलती है । 1984 ई0 में कजरा बांध परियोजना बनायी गयी थी । जिसमें हरिपुर से तिरवाहा तक जो बांध है, 2017 की बाढ़ में पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया । महोदय, लाखों हेक्टेयर जमीन में किसानों ने अपने बीज और फसल को लगाया हुआ था, 2017 से आज तक उस बांध का निर्माण नहीं होने से काफी किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है । हम चाहेंगे अपने बिहार के मंत्री जी से कि इस काम को अमलीजामा पहनाकर उस क्षेत्र के किसान के दर्द को समझेंगे । सभापति महोदय, हमारे यहां बथनाहा से अररिया तक एक नहर जाती है जो एबीसी नहर के नाम से जाती है । उस नहर पर पिछली बार रोड का निर्माण कराया गया था, जो सड़क 12.4 फीट चौड़ाई के अंतराल में है । पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत, उसे हमने आग्रह करके विभाग को भेजा है । हम माननीय मंत्री जी से चाहेंगे कि एबीसी नहर जो बथनाहा से अररिया को जाती है, उस सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए अपना समर्थन दीजिये ।

सभापति(श्री अवध विहारी चौधरी) : माननीय सदस्य, आपका समय पूरा हो गया, आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री विद्यासागर केशरी : माननीय सभापति महोदय, हमारे ही विधानसभा क्षेत्र में कुछ छोटी-छोटी आवश्यकताएं हैं, उसमें मैं आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं । आजादी से पहले नहरों के दोनों किनारों पर बसावट कम हुआ करती थी और आज जब जनसंख्या की वृद्धि हुई, तब नहरों के दोनों किनारों पर काफी मात्रा में लोगों की बसावट हो गयी है और जो योजनाएं पहले, जो नहरों पर पुल निर्माण की बात हो रही थी, उसमें 2 किमी के रेडियस के उपरांत ही कहीं नहर पर पुल बनाना था ।

सभापति (श्री अवध विहारी चौधरी) : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें । आपका समय पूरा हो गया है ।

श्री विद्या सागर केशरी : सभापति महोदय, बस एक मिनट । कम-से-कम उन स्थानों पर जहां एक हजार की आबादी हो, वैसे सभी स्थानों पर जल संसाधन विभाग पुल का निर्माण कराये ताकि बहुत दूरी तय कर छात्र-छात्राओं को या किसानों को अपने खेत का माल या आवागमन करने में जो दिक्कतें आती हैं, उसका निदान हो ।

सभापति महोदय, आपने जो मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार ।

सभापति (श्री अवध विहारी चौधरी) : माननीय सदस्य, श्री प्रहलाद यादव जी ।

श्री प्रहलाद यादव : सभापति महोदय, आज जो जल संसाधन विभाग का बजट प्रस्तुत किया गया है उसके विरोध में और कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ । महोदय, भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार दो भागों में बँट जाता है...

सभापति (श्री अवध विहारी चौधरी) : माननीय सदस्य, आपका समय दस मिनट है ।

श्री प्रहलाद यादव : सभापति महोदय, नहीं, मेरा पंद्रह मिनट समय है ।

सभापति (श्री अवध विहारी चौधरी) : नहीं, इसमें लिखा हुआ है । इसलिए, आप समय-सीमा के अंदर बोलें ।

श्री प्रहलाद यादव : ठीक है । अगर घट गया तो वह भी घट जाय, हम छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है । घट गया, कैसे घट गया ?

दो भागों में बँटा हुआ है । एक तो बाढ़ से तबाह होता है और दूसरा सुखाड़ से तबाह होता है और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हर खेत में पानी देना है । अब कैसे पानी देंगे, यह तो हम नहीं बता सकते हैं । यह स्थिति है एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ सुखाड़, तो निश्चित रूप से बाढ़ का निदान आज तक नहीं हुआ है । बहुत ज्यादा इस पर बहस भी हुई है, बहुत तरह की बातें आयी हैं लेकिन बाढ़ का निदान नहीं हुआ । इसलिए, हम चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े तो निश्चित रूप से बाढ़ का निदान होना चाहिये और जो सुखाड़ का एरिया है दक्षिणी बिहार, उसके लिये भी सिंचाई की सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिये । सबसे बड़ी बात है कि इस विभाग में हैंड की कमी है, पैसा तो ठीक है बजट में आ गया है, उस पैसे को खर्च करने के लिये इनके पास उतने हैंड नहीं हैं । एक-एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर कई एक क्षेत्रों को कवर करते हैं, ये खर्च कैसे करेंगे, खर्च करने के लिये तो हैंड होना चाहिये लेकिन इनके पास हैंड नहीं है । यह स्थिति है, तो निश्चित रूप से इस पर विचार करना होगा । मैं लखीसराय जिला के संबंध में बताना चाहता हूँ, वहां पर मुख्य रूप से तीन डैम हैं । एक मोरवे डैम है, दूसरा, बासकुंड डैम है और तीसरा, लोअर किऊल जलाशय योजना (एल0के0वी0)। तो एक दायां भाग कुंदर से बंदवचक्तता, उसका तो आर0सी0सी0 हो गया लेकिन उसको और बढ़ाना था, वह पूरा नहीं हुआ था । बासकुंड की जो स्थिति है, वह बहुत बड़ा डैम है, बहुत पुराना हो गया है लेकिन उस पर विभाग की कोई नजर नहीं है, इसलिए उस पर ध्यान दिया जाय और उस डैम से पक्का नाला निकाल कर, जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है उसको वहां तक पहुँचाया जाय ।

(क्रमशः)

टर्न-17/सुरज-संगीता/02.03.2021

...क्रमशः...

श्री प्रहलाद यादव : और उस डैम से पक्का नाला निकालकर जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है उसको वहां तक पहुंचाया जाये । मोरवे डैम की भी वही स्थिति है । डैम बहुत बड़ा है और बहुत पुराना है लेकिन उसका आज तक जीर्णोद्धार सही ढंग से नहीं हुआ है, बहुत बड़ा एरिया है और उस डैम से जो नहर निकली है बहुत दूर तक कजरा होते, अरमा होते गया है लेकिन है

क्या वह कच्ची नहर है ? कच्ची नहर रहने के कारण जब पूर पानी उसमें फोर्स के साथ बहना शुरू होता है तो जहां-तहां टूट जाता है इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि अगर सही में पानी देना चाहते हैं हर खेत में तो निश्चित रूप से उसको भी जिस तरह से कुंदर से बन्नु बगैइचा दियर तक आपने पक्कीकरण किया नहर को उसी तरह से इसको भी पक्कीकरण कीजिए लेकिन एल0के0भी0 का बायां भाग जो हल्सी रामगढ़ होते मोरमा तक जाता है वह अभी भी कच्ची है उसको भी हम चाहेंगे कि उसको भी पक्कीकरण किया जाय ताकि एक बार पक्कीकरण हो जाने के बाद बार-बार उसमें मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च नहीं होगा । बन जाने के बाद यह स्थिति वहां है जो मुख्य रूप से सिंचाई की व्यवस्था वहां पर है उसमें दिक्कत और क्या है जो मेन नहर से ब्रांच नाला निकाला है, छोटा-छोटा नाला निकला है जो खेत का पटवन करता है वह सारा का सारा एकदम ध्वस्त है बिल्कुल जर्जर स्थिति में है जिसके कारण पानी अगर फूल आता है करेंट के साथ तो निश्चित रूप से वह पानी जो है बर्बाद हो जाता है फिर बहकर के वह पानी खेत में नहीं जाकर के कहीं-कहीं चला जाता है इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ये जो भी छोटा-छोटा मेन नहर से जो नाला निकला है उसका पक्कीकरण किया जाय और एक हमारे क्षेत्र में टाल है वह मुंगेर और सूर्यगढ़ा प्रखण्ड के बीच में, बहुत बड़ा टाल है और उसमें बहुत ज्यादा दलहन होता है जिस तरह से बड़हिया मोकामा उतना बड़ा तो नहीं है उससे थोड़ा छोटा है लेकिन उसमें दिक्कत क्या है जब भी वर्षा होगा तो पानी जमा हो जाएगा और पानी जमा हो जाने के बाद क्या होता है कि समय पर खेती नहीं हो पाता है क्योंकि पानी जमा होने पर निकलता ही नहीं इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि उस टाल में जो पानी जमा होता है उसका निकासी होना चाहिए । दूसरी बात है कि किऊल से सुरक्षा बांध गया है वह सूर्यगढ़ा होते मेदनीचौक से होते रसलपुर होते मुंगेर चला गया है और रसलपुर के बगल में और मुंगेर सीमा के बीच में वहां पर बांध नहीं है जिसके कारण हर साल जब भी बाढ़ आती है उस छोर से पूरे गांव के फसल को हर साल बर्बाद कर देता है इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि जो सुरक्षा बांध बचा हुआ है उसको भी थोड़ा बढ़ा करके बनवाया जाय । किऊल नदी से बहुत सा गांव उसके बगल में बसा हुआ है । वहां बराबर वर्षा के समय में जब पानी ज्यादा आता है तो गांव के बगल से कटाव शुरू हो जाता है सूरजीचक हुआ, राहतपुर हुआ, नीस्ता हुआ उसके बाद आगे चल करके हुसैना उसके बाद भलुई, उसके बाद है गोड्डी, घोसीकुन्डी, मोहनकुंडी ये सारे इलाके जो हैं वे किउल के किनारे बसे हुए हैं और पानी के बहाव में बराबर उस किनारे से हमेशा कटाव होता है इसीलिए ये सारे जितने भी कटाव होते हैं निश्चित रूप से उसको कटाव को बांधने के लिए, कटाव से उस गांव को बचाने के लिए निश्चित रूप से सुरक्षा बांध की व्यवस्था हो

। यहां तक कि बहुत से ऐसे जैसे हुसैना गांव है सूर्यगढ़ा प्रखंड में, चंदनिया गांव है, इस तरह के कई गांव है, जब पानी आता है जिसके कारण पूरा का पूरा गांव पानी से डूब जाता है और उसका चूंकि निकास नहीं है अगर इन सारे गांवों में नाला के द्वारा अगर किऊल नदी के बगल में जो बांध है...

सभापति (श्री अवध बिहारी चौधरी) : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ, कृपया आसन ग्रहण कीजिए ।

श्री प्रहलाद यादव : महोदय, एक दो मिनट और बोलने दीजिए ।

सभापति (श्री अवध बिहारी चौधरी) : अब आप आसन ग्रहण करें । अपने क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में सरकार का ध्यान आपने आकृष्ट कर दिया है इसलिए अब...

श्री प्रहलाद यादव : सभापति जी, अभी तो अधूरा ही है ।

सभापति (श्री अवध बिहारी चौधरी) : अब आप स्थान ग्रहण करें । अन्य सदस्यों को भी समय देना है ।

श्री प्रहलाद यादव : ठीक है सभापति जी, आपका आदेश है, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं चूंकि मेरे समय को काटा गया है, यह ठीक नहीं हुआ है ।

सभापति (श्री अवध बिहारी चौधरी) : बहुत-बहुत धन्यवाद । श्री रत्नेश सादा ।

श्री रत्नेश सादा : सभापति महोदय, मैं जल संसाधन विभाग के बजट भाषण के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, जल संसाधन वह विभाग है, जिस विभाग के कारण बिहार के ही नहीं अपितु देश-दुनिया जल संसाधन विभाग के ऊपर निर्भर करती है । जैसे किसान को पटवन के लिए जल की ही आवश्यकता होती है और पेड़-पौधे से लेकर कीट-पतंग, पशु-पक्षी, मनुष्य का भी जल के बगैर जिन्दा रहना असंभव बात है । महोदय, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जब जल भू-गर्भ की गहराई अधिक होने लगी तो उन्होंने हार्वेस्टिंग के तहत जल संचय का कार्यक्रम चलाया, जो वर्षा जल से भूगर्भ जल में संचित करने का काम किया । महोदय, इस योजना के तहत वर्ष 2021 के पूर्व की तैयारी जो है, बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य 270 अदद सुरक्षा की योजना है, जिसमें लगभग 1 करोड़ 2 लाख 25 हजार करोड़ रुपया खर्चा हो गया । महोदय, सुपौल और मधुबनी में कोशी नदी के पश्चिमी किनारे को ऊंचीकरण करने के लिए इस योजना में 116.36 करोड़ रुपये की योजना का प्रावधान किया गया है, जो कार्य प्रारंभ है महोदय । महोदय, सीतामढ़ी में रातो नदी के तट पर 110.65 करोड़ की योजना से बाढ़ प्रबंधन की योजना में वर्ष 2022 तक पूरा कराया जायेगा । महोदय, भागलपुर के गंगा नदी के बाएं तट पर जाह्नवी चौक से इस्माइलपुर तटबंध निर्माण के लिए 42.42 करोड़ रुपया खर्च किए जायेंगे । बिहार के नदियों को जोड़ने की योजना है, कोशी बेसिन

नदी, महानंदा बेसिन में कोशी मेशी का इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस के लिए केंद्र सरकार ने 08.12.2020 को मान्यता दे दी है ।

क्रमशः

टर्न-18/ मुकुल-राहुल/02.03.2021

क्रमशः

श्री रत्नेश सादा: महोदय, मधुबनी जिला के जय नगर कमला नदी पर निर्मित वीयर को बराज में परिवर्तन करने हेतु 405.66 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है । महोदय, हर खेत में जल का प्रबंध का लक्ष्य है, सात निश्चय पार्ट-2 के तहत किसानों को कृषि के लिए पानी की व्यवस्था करने का काम किया है, जो बिजली मीटर लगाने के लिए किसानों को दी जा रही है । महोदय, वर्ष 2020-21 में अब तक 1095 कार्य पूर्ण किया गया है इस योजना में 90,830 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता तथा 591.17 लाख हेक्टेयर घन मीटर जल संचय कराने की क्षमता सृजित की गई है । महोदय, 564 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है । महोदय, खनन क्षेत्र से प्राप्त राजस्व के मामले में बिहार राज्य द्वारा तीव्र विकास किया गया है, महोदय, वर्ष 2019-20 में वार्षिक लक्ष्य 1600 करोड़ के विरुद्ध 1616.25 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली की गई है । महोदय, वित्तीय वर्ष दिसम्बर, 2020 तक निर्धारित लक्ष्य के 800 करोड़ रुपये के विरुद्ध 807.48 करोड़ रुपये वसूली की गई है । महोदय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग खनन विभाग में व्यापक स्तर पर किया जा रहा है । महोदय, इसके फलस्वरूप राजस्व संग्रह में अपेक्षित वृद्धि के साथ-साथ अवैध खनन पर प्रभारी कार्य नियंत्रण स्थापित किया जायेगा । महोदय, इस क्रम में विभाग में एक आधुनिक पी0एम0यू0 गठित किया गया है जिसके द्वारा लघु खनिज एवं परिवहन हेतु निर्गत किये जा रहे हैं । चालान पर नियंत्रण रखा जा रहा है । महोदय, पशु एवं मत्स्य विभाग में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं रोजगार/स्वरोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका है इस विभाग में महत्वपूर्ण उपलब्धि निम्न प्रकार हैं:-

पशुओं के स्वास्थ्य एवं बीमारियों से रोकथाम हेतु विभिन्न प्रकार के टीकाकरण का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है । इसके तहत गत वर्ष खुरहा एवं मुँहपका रोग (एफ0एम0डी0) के विरुद्ध दो चरणों में कुल 330.73 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया है । महोदय, गलाघोंटू(एच0एस0) एवं लंगड़ी बुखार (बी0क्यू0) रोग के विरुद्ध कुल 165 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया है । महोदय, भेड़-बकरियों की सुरक्षा हेतु पी0पी0आर0 रोग के विरुद्ध टीकाकरण कार्यक्रम चलाकर कुल 109.87 लाख भेड़-बकरियों को टीकाकृत किया गया है । इसके अतिरिक्त चार-आठ माह के बाछियों/पाड़ियों को ब्रुसेलोसिस रोग से बचाव हेतु कुल 10.98 लाख पशुओं का

टीकाकरण किया गया है । महोदय, कुछ हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं जो इस बार के चुनाव के मुद्दे में मुख्य मुद्दे थे । वे क्षेत्रीय समस्याएं हैं, हमारे सोनवर्षा विधान सभा के सोनवर्षा प्रखंड के शाहपुर पंचायत में हरिपुर चॉप है जो हजारों एकड़ जमीन जल-जमाव से ग्रसित है । विराटपुर पंचायत के भादा चॉप जो 2,000 एकड़ जमीन किसानों का जल-जमाव से ग्रसित है, सहसौल पंचायत के स्वेत कमल दह चॉप जो है लगभग 3,000 एकड़ में जल-जमाव है, इसकी जल निकासी की व्यवस्था की जाय । देहद वेहट पंचायत के देहद चॉप में जल निकासी की व्यवस्था की जाय, महुआ पंचायत के महुआ चॉप की जल-निकासी की व्यवस्था की जाय । परड़िया पंचायत के परड़िया चॉप के तहत फतेहपुर चॉप की जल-निकासी की व्यवस्था की जाय । कोपा पंचायत के भस्ती विन्द टोली पचादी चॉप की जल निकासी की व्यवस्था की जाय । महोदय, सहरसा जिला के महिषी विधान सभा के बलुआ पुल है, बलुआ पुल के पश्चिम नदी के किनारे से लेकर रसलपुर तक सुरक्षात्मक बांध की व्यवस्था की जाय, नहीं तो पुल पर असर पड़ेगा ही और लाखों किसान बेघर हो रहे हैं । माननीय सभापति महोदय, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से से जल संसाधन मंत्री जी से मांग करता हूं, ।

सभापति (श्री अवध बिहारी चौधरी): माननीय सदस्य, श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव: माननीय सभापति महोदय, आज मैं जल संसाधन विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । सभापति महोदय, सरकार के जल संसाधन विभाग की विफलताओं के बारे में विस्तार से हमारे बड़े भाई सुधाकर जी ने बताने का काम किया । सत्ता पक्ष के साथियों के द्वारा बोला जाता है कि कटौती प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और फिर योजना की स्वीकृति के बारे में बोला जाता है कि पैसा खर्च करने की क्षमता नहीं और फिर कटौती प्रस्ताव पर भी टीका-टिप्पणी होती है । सभापति महोदय, मैं बिहार के उस इलाके से आता हूं जहां सिंचाई के मामले में एक तरफ उत्तर बिहार जो बाढ़ की चपेट में और दक्षिण बिहार जो सुखाड़ की चपेट में आजादी के 70 साल बाद भी आज वही हालत है । सभापति महोदय, हम मगध से आते हैं जहां कभी अमर शहीद जगदेव प्रसाद जैसे जन नेताओं ने हमीदनगर पुनपुन सिंचाई परियोजना की परिकल्पना की थी । पिछली बार भी हमने सदन में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट कराया था हमीदनगर पुनपुन परियोजना की तरफ । सभापति महोदय, मगध की वह काफी महत्वपूर्ण परियोजना है । सभापति महोदय, करीब सरकार का अरबों रुपया खर्च होकर के वह योजना आज तक अधूरी पड़ी हुई है । हम इस सदन में जिस सरकार में आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी नेतृत्व कर रहे थे और मेरे पिता मुद्रिका सिंह यादव जी के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर उसकी स्वीकृति मिली थी लेकिन आज वर्तमान सरकार जिसको 15 साल से अधिक समय हो गया है कई बार हमीदनगर पुनपुन सिंचाई

परियोजना के बारे में तारांकित प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया । महोदय, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल-जीवन-हरियाली पर चर्चा की थी जब पूरा बिहार सुखाड़ की चपेट में था और मध्य बिहार का इलाका, गया, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, पटना में जिस समय पानी की किल्लत हो रही थी उस समय जलवायु परिवर्तन पर एक चर्चा हो रही थी महोदय, उस समय हमने बताया था कि अगर हमीदनगर पुनपुन सिंचाई परियोजना को कार्यान्वित कराकर के उसका जो ध्येय था कि उसमें बैराज लगाकर के और फिर मोरहर, दरधा, फल्गू में पानी गिराकर के उसको बांधा जाय तो उस इलाके के किसानों के चेहरों पर खुशहाली होगी, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक कोई भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गंगा के पानी को बोधगया ले जाने की जो योजना बनाई गई, उल्टी धारा बहाने का, हमने उस समय भी ध्यान आकृष्ट कराया था माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, मंत्री जी को भी कि उसी पुनपुन के पानी को अगर बोधगया ले जाया जाय तो इस इलाके में सभी खेतों को पानी भी मिलेगा और जलस्तर में जो गिरावट हो रही है उसकी भी पूर्ति होगी ।

क्रमशः

टर्न-19/यानपति-अंजली/02.03.2021

...क्रमशः..

श्री कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादवः सभापति महोदय, हमारे यहां इलाके में उदेरा स्थान जो बराज है उसका भी पूर्ण रूप से अगर उस पर भी काम हो तो हमारे यहां मकदुमपुर के इलाके में, घोसी के इलाके में, काको के इलाके में उससे सिंचाई होगी । हमारे यहां पंचतीर्थ पुनपुन में बीयर बांध बनाया गया जिसकी ऊंचाई कम रहने के चलते जो उससे पानी निकलता था वह नहीं निकल रहा है । महोदय, हमने सदन का ध्यान भी उस समय आकृष्ट कराया था पिछली सरकार में ही कि उसकी अगर पुनपुन तीर्थ बांध को अगर ऊंचा कर दिया जाय तो वहां से जो बांध लगा है, उसकी उपयोगिता बढ़ेगी और हमारे रतनी इलाका में और जहानाबाद प्रखण्ड के कुछ इलाकों में और मसौढ़ी विधान प्रखण्ड के इलाके में उसकी सिंचाई होगी । महोदय, हमारे यहां नसरतपुर बीयर बांध है, सुगौर बीयर बांध है, जामुक बीयर बांध है, फरीदपुर रेगुलेटर है, मिल्की स्लुईश गेट है, हमीदपुर रेगुलेटर है, कश्मा रेगुलेटर है और इन सभी रेगुलेटरों की हालत बद से बदतर है । महोदय, चूंकि कई वर्षों से बारिश नहीं होने के चलते पानी का आना-जाना नहीं हो रहा था । महोदय, हम उपर्युक्त अधर में लटके सभी महत्वपूर्ण योजनाओं की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं । महोदय, उदेरा स्थान बराज, हमीदनगर, पुनपुन सिंचाई परियोजना एवं पुनपुन

तीर्थ बांध को जोड़ दिया जाय तो जहानाबाद, अरवल, पटना, मसौढ़ी क्षेत्र के लोग खुशहाल हो जाएंगे महोदय और मखदुमपुर एवं रतनी फरीदपुर प्रखंड के किसानों के खेतों में जो पानी नहीं जा रहा है महोदय उससे पानी जाने लगेगा । महोदय, उदेरा स्थान जो बीयर बांध है, सुगौर बीयर बांध से जोड़ा जाय और जहानाबाद जिला के तीन प्रखंड जहानाबाद, काको, मखदुमपुर आंशिक खेती तक पानी पहुंचाया जा सकता है महोदय और किसानों के चेहरे पर खुशहाली होगी । महोदय, दक्षिण बिहार के किसानों एवं मजदूरों के पलायन को भी रोका जा सकता है । महोदय, हजारों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकती है । महोदय, खेतों, आहर और पईन आ जाने से भूजल स्तर में जो गिरावट हो रही है....

सभापति(श्री अवध विहारी चौधरी): माननीय सदस्य आपका मात्र दो मिनट बचा हुआ है इसलिए अपनी बात को जो आवश्यक हो उसको रखिए, सरकार का ध्यान आकृष्ट कीजिए ।

श्री कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव: सभापति महोदय, हम वही ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं हमारे अपने क्षेत्र के बाहर का नहीं है । लेकिन जो महत्वपूर्ण योजना है हमीदनगर पुनपुन सिंचाई परियोजना हम देख रहे थे सिंचाई विभाग का बजट, उसमें उस पर किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं है । हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री महोदय अपने भाषण में उस हमीदनगर पुनपुन सिंचाई परियोजना का भी उल्लेख करें क्योंकि हमारे यहां मध्य बिहार के किसान और मध्य बिहार के किसानों के पास जो खेती है वह काफी उपजाऊ है, समतल है । महोदय, अगर उसके खेतों में पानी जाएगा तो उनके चेहरे पर खुशहाली होगी और पलायन बंद होगा ।

सभापति(श्री अवध विहारी चौधरी): अब आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव: हम आसन के प्रति आभार प्रकट करते हैं । धन्यवाद ।

सभापति(श्री अवध विहारी चौधरी): श्रीमती रश्मि वर्मा जी ।

श्रीमती रश्मि वर्मा: सभापति महोदय, मैं जल संसाधन विभाग के बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं । बिहार एक जल संपदा से परिपूर्ण राज्य है जैसा कि हम सभी जानते हैं । एक तरफ जहां नदियों का जाल है वहीं दूसरी तरफ नदियों से सिंचित होनेवाली नहरों का भी जाल मौजूद है वर्षों पूर्व इन नहरों को किसानों के हित में उनके फसलों को सिंचित करने के लिये बनाया गया था । इसका जीर्णाद्धार होने से तथा इसका विस्तार होने से जल संसाधनों का और अधिक उपयोग किया जा सकता है जिसका परिणाम होगा हमारे राज्य में बाढ़ एवं सूखा जैसी स्थिति के प्रकोप से बचाव । मैं जिन क्षेत्र चंपारण का प्रतिनिधित्व करती हूं वह क्षेत्र अरसे से अपने जल संसाधन एवं इनके प्रबंधन के लिये प्रसिद्ध रहा है । वर्षों पूर्व यहां पर गंडक पर बराज बनाकर हमारे देश के इंजीनियर्स ने अपने अद्‌भुत करामात को दिखाया है । भारत और नेपाल की मित्रता को एक आयाम देते हुए स्वराज की स्थापना की गयी । कालांतर में इसका भरपूर उपयोग सिंचाई के लिये भी किया गया

। अब ये बराज जीर्णोद्धार की बाट जोह रहा है । सदन के माध्यम से मैं आप सभी को इसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है यह बताना चाहती हूं यदि ससमय इस बराज के पिलर्स एवं उनके फाटकों का जीर्णोद्धार नहीं किया गया तो भविष्य में कुछ अनिष्टकारी घटनाएं भी हमलोग झेल सकते हैं । यहां पर मौजूद गाद की सफाई एवं यहां से शुरू हो रही नहरों के जालों का समुचित प्रबंधन आज की अत्यंत आवश्यक मांगों में से एक है जैसा कि हम सभी जानते हैं इन नहरों से एक बड़े भूभाग की खेती का सिंचन किया जाता है हर साल आनेवाली प्रलयंकारी बाढ़ का प्रबंधन भी इन नहरों के माध्यम से किया जा सकता है । यदि इनकी ट्रिब्यूटरीज तक हम इनके कुशल प्रबंधन को नये टेक्निक के साथ पूर्ण करें तो इन नहरों के प्रबंधन में जो मुख्य परेशानियां आयेंगी उनमें नदियों का क्षरण, रैट हॉल्स का बनना और स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा इसपर अतिक्रमण किया जाना इत्यादि अनेक परेशानियां आ सकती हैं । इन छोटी छोटी समस्याओं का भी हल है । मेरी समझ से यदि हम अपने दृष्टिकोण से थोड़ी व्यवहारिकता लाएं तो ये परेशानियां दूर हो जायेंगी । मैंने वर्षों से इन नहरों को अपने क्षेत्र में देखा है शुरू से मेरे मन में यह भाव रहा है कि नहरों के बेहतर बेकार पड़े विभागों पर यदि कुछ ऐसी योजनाओं को प्रारंभ किया जाय जिससे नहरों की जमीन भी बचे और मिट्टियों का क्षरण भी न हो तो इन नहरों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है । मेरे अनुसार मैं यहां सदन का ध्यान आकृष्ट करूंगी मेरे अनुसार यदि नहर के दोनों तरफ बांधों के किनारे यदि फूलों की खेती की जाय तो मिट्टी का क्षरण भी कम होगा साथ ही स्थानीय लोगों को बेहतर रोजगार भी उपलब्ध हो सकता है । आज हम फूलों के लिये पूर्णत: पश्चिमी बंगाल पर निर्भर हैं यदि हमारे स्थानीय कर्मवीर इन नहरों के किनारे बांध पर फूलों की खेती करते हैं इससे हमारे आत्मनिर्भर भारत एवं बिहार का सपना साकार होगा । दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वह हमारी बिजली है ऊर्जा है । बिजली की खरीद एवं उत्पादन में हो रही लगातार वृद्धि एवं उसकी मार झेल रहे नागरिकों को एक राहत गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्रियान्वयन से दिया जा सकता है । यह कांसेप्ट मुझे ऊपर बिजली नीचे मछली की प्रेरणा स्वरूप मिला है कि क्यों न नहरों के ऊपर सौर ऊर्जा के प्लेट्स को कुछ इस तरह से व्यवस्थापित किया जाय कि नहरों के मूल उद्देश्य भी परिपूर्ण हो जायं और उनके उपलब्ध भूभाग पर सोलर प्लेट्स का अधिस्थापन किया जा सके ।

सभापति(श्री अवध विहारी चौधरी): माननीय सदस्या, आपका समय समाप्त हुआ, आप स्थान ग्रहण करें ।

श्रीमती रश्मि वर्मा: महोदय, मुझे दस मिनट का समय था मैं उसी हिसाब से प्रिपेयर कर रही थी ।

सभापति(श्री अवध विहारी चौधरी): नहीं, आपका दो मिनट ही समय था ।

श्रीमती रश्मि वर्मा: महोदय, वह बहुत महत्वपूर्ण विषय है यदि मुझे दो मिनट का या एक मिनट का भी समय दिया जाय तो बहुत ही लाभदायक विषय पर कुछ चर्चा आगे भी हो सकती थी।

सभापति(श्री अवध विहारी चौधरी): बोला जाय ।

श्रीमती रश्मि वर्मा: जी धन्यवाद । नहरों का मूल्य देश भी पूर्ण होगा और उसके उपलब्ध भूभाग पर सोलर प्लेट्स का अधिग्रहण किया जा सके जो स्थानीय बिजली की आपूर्ति से परिपूर्ण कर सकेंगे हमलोग । यहां इस बात को मैं उल्लेख करना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में देश का सबसे बड़ा नहर ऊर्जा के इकाई कार्य करना प्रारंभ कर दिया है तो क्या हम भी अपने उज्ज्वल भविष्य के लिये सौर ऊर्जा प्रबंधन पर कोई ठोस कदम उठायें जिससे न सिर्फ स्थानीय ऊर्जा की मांग को पूरा किया जा सके बल्कि ऊर्जा पर होनेवाले व्यय को भी बचाया जा सकता है । इन दो आयामों के अलावा यहां नियमित रूप से नहरों में पानी हमेशा मौजूद रहता है यह भी ध्यान देने योग्य है । उसमें पैन कल्चर के माध्यम से मत्स्य उत्पादन का भी कार्य किया जाय तो मत्स्य उत्पादन में हो रही वृद्धि साथ ही स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार भी मिल सकता है और सिंचित होनेवाले पानी से मछलियों का.....

सभापति(श्री अवध विहारी चौधरी): आप समाप्त करें, आपका समय खत्म हो गया और माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह जी ।

श्रीमती रश्मि वर्मा: जी, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

टर्न-20/सत्येन्द्र/02-03-2021

श्रीमती रश्मि वर्मा:(क्रमशः) नहरों का मूल उद्देश्य भी पूर्ण होगा और उसके भू-भाग पर सोलर प्लेट को अधिष्ठापित किया जा सकता है जिससे स्थानीय बिजली को परिपूर्ण कर सकेंगे । यहां इस बात का मैं उल्लेख करना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में देश के सबसे बड़ा नहर ऊर्जा इकाई कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है तो हम भी अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए सौर ऊर्जा प्रबंधन पर कोई ठोस कदम उठायें जिससे न सिर्फ स्थानीय ऊर्जा की मांग को पूरा किया जा सके बल्कि ऊर्जा पर होने वाले व्यय को भी बचाया जा सकता है। इन दो के अलावा यहां के नहरों में पानी हमेशा मौजूद रहता है जिस कारण हमें यह भी ध्यान देने योग्य है जहां मत्स्य उत्पादन का कार्य भी किया जाय तो मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के साथ स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार भी मिल सकता है और सिंचिंत होने वाली पानी से..

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी): अब समाप्त करें। आपका समय समाप्त हो गया।

अब माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह।

श्री अजय कुमार सिंह: सभापति महोदय,जो भी मैं देख रहा था, बजट में जो प्रावधान है कोई भी कार्यक्रम जब तय होता है तो उसका सर्वे होता है..

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी) :माननीय सदस्य,आपका समय आवंटित है मात्र 7 मिनट।

श्री अजय कुमार सिंह: 7 मिनट।

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी) :जी,7 मिनट।

श्री अजय कुमार सिंह: तो बिहार में जैसी मुझे जानकारी है कि कृषि के क्षेत्र में जो विभाजित है उसके जोन-2 एवं जोन-3 में, तो जल संसाधन विभाग को उसके मुताविक योजनाओं को लेना चाहिए था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूॅं कि साहेबगंज से लेकर बक्सर तक का जो ड्रायर पार्ट है वहां 1100-1200 एम0एम0 वर्षा होती है, ये मानना है लेकिन इधर के वर्षो में 400 एम0एम0, 500 एम0एम0, 700 एम0एम0 वर्षा होती है ऐसी स्थिति में जब मौसम का मिजाज बदलता है तो किसान परेशान हो जाता है, चिन्तित हो जाता है । इसके संबंध में मेरा यह कहना है कि देखा है मैंने कि यहां से पानी ले जाया जायेगा राजगीर पीने के लिए तो बाढ़ के समय में जब टाल में पानी स्वत: आ जाता है तो हमारे मुंगेर जिले में दो डैम है एक है कुंड जलाशय दूसरा सतघरवा जलाशय, उस बाढ़ के पानी को लिफ्ट कर के उसमें डाला जाता तो किसानों को लाभ होता, इसके संबंध में हमारे यहां एक डकरा प्रोजेक्ट है जो बहुत पहले आया था जिसके थर्ड फेज में गंगा का पानी उसमें डालने की व्यवस्था थी, एक तो यह हो गया कि डैम में अगर गंगा के पानी को ले जाकर हम भर दें, चूंकि 400 एम0एम0, 500 एम0एम0, 700 एम0एम0 वर्षा होने के बाद भी जलग्रहण क्षेत्र में उतना पानी रहेगा ही नहीं इसलिए ऐसा होने से उसमें पानी रहेगा तो किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी। हमारे ही जिले में तारापुर विधान-सभा क्षेत्र में वरूआ नदी है जिसमें बालू के उठाव से उसका लेवल घट गया है। पहले जब बालू का उठाव नहीं होता था तो किसान धीरे धीरे वहां से छेक कर पानी अपने खेत में ले जाते थे लेकिन अब वहां बालू के उठाव से कोई उपाय ही नहीं रह गया है कि नदी के बगल के खेतों में पानी ले जाया जा सके तो वहां भी किसानों के मुताविक अगर चेक डैम का निर्माण होता तो पानी का लेवल बराबर होता और उनके खेत में पानी चला जाता। मेरे जिले में बहुत सी ऐसी योजनाएं है जैसे नहर को भरकर उस पर सड़क बना दी गयी है तो कल मैंने चीफ इंजीनियर से पूछा कि भाई इसका एन0ओ0सी0 आपने दिया है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं है तो सड़क बनाने वाला आपका ग्रामीण कार्य विभाग जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर से एन0ओ0सी0 नहीं लेता है जिससे सिंचाई सुविधा बाधित होती है । ऐसे 2-3 जगहों पर मैंने देखा है कि इनलोगों ने सड़क बना दिया, नाला को ही भरकर सड़क बना दी गयी, जो सर्वे के नक्शा में नाला था उसको खड़गपुर झील की तरफ से बनाया गया था तो

इसका भी तालमेल होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या जो जोन-3 सेक्टर है हमारा, पठारी इलाका जो है उसमें बहुत चेक डैम तो है हमारे यहां, एक सिंधवारिणी कम्पलेक्श बना था इसमें गयघट और तीनों योजनाओं को मिलाकर एक सिंधवारिणी कम्पलेक्श कहा गया था लेकिन कुछ पार्ट उसका जंगल विभाग में आने के कारण बाधित हो गया, काम नहीं हुआ तो जल संसाधन विभाग पठारी इलाके के लिए ऐसी योजनाओं को चिन्ह्ति कर के और इस पर अनापत्ति पत्र सरकार के रास्ते जो होना चाहिए। इसमें देखा है कि भागलपुर के तटबंध के किनारे दीवाल देने के प्रावधान है, मैंने अपने तारांकित प्रश्न में भी पूछा था कि भाई मुंगेर जिला में जो बसावट है गंगा के किनारे, यहां हर साल एक फीट, दो फीट का कटाव हो जाता है बसावट के इलाके में, इसमें भी व्यवस्था हो, मैंने मांग किया था कि यह होना चाहिए। महोदय, थोड़ी देर पहले चर्चा हुई कि बाढ़ का पानी टाल में जमा हो जाता है, दूबे जी ने भी चर्चा किया कि जहां तहां फंस जाता है तो हमारे यहां भी फंसता है और रिहायशी इलाके में भी पानी फंस जाता है जिसके कारण 5-6 पंचायतों में ऐसा होता है लेकिन ऐसी स्थिति में भी उस इलाके से पानी निकालने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है।

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी)माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री अजय कुमार सिंह: धन्यवाद।

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी): अब मैं श्री राजेश कुमार सिंह जी को, जिनका समय आवंटित है 7 मिनट। श्री राजेश कुमार सिंह जी।

श्री राजेश कुमार सिंह(क्षेत्र सं0-137): अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और साथ ही मैं मोहिउद्दीनगर से चुनकर आया हूँ तो मैं वहां के जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जल संसाधन के अनुदान की मांग पर विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2000 में झारखंड को बिहार से अलग होने के बाद बिहार का भू-भाग दो भागों में दिखता है- एक बाढ़ का मैदानी भाग और दूसरा कृषि योग्य भूमि। सभापति महोदय, बिहार का जलीय श्रोत 15 नदियों के प्रवाह प्रदेश में विभाजित है, राज्य का उत्तरी मैदान धरातलीय एवं भूमिगत दोनों दृष्टि से सम्पन्न है। गंगा के दक्षिणी मैदान को उपयोग में लाने हेतु जल संसाधन की मात्रा उतरी बिहार की तुलना में कम है किन्तु इस भाग में जल संसाधन के अपेक्षाकृत अधिक उपयोग हुआ है। हिमालय, छोटानागपुर का पठार तथा विंध्याचल की पहाड़ियों से उतरने वाली कई नदियों की जल धारा गंगा में विसर्जित होती है। सभापति महोदय, यह गंगा नदी हमारे प्रदेश में लगभग बीचों बीच में बहती है । उत्तरी बिहार का समतल क्षेत्र घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, अवधारा, कमला, कोशी और महानंदा नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, क्यूल, हरेहर, चंदन

और चिर नदियों का प्रवाह प्रदेश बिहार के दक्षिणी भाग में बहने वाली नदियां हैं। सभापति महोदय वर्षा के दिनों में उत्तर बिहार की नदियों में बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है । इस 445 कि0मी0 लंबी गंगा का कुल प्रवाह क्षेत्र 19322 वर्ग कि0मी0 है। (क्रमशः)

टर्न-21/मधुप/02.03.2021

..क्रमशः..

श्री राजेश कुमार सिंह : जिसमें 12920 वर्ग किलोमीटर बाढ़ से प्रभावित होता है । इसी तरह कोसी नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र 11410 वर्ग किलोमीटर है जिसमें 10150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है । पुनपुन के 9026 वर्ग किलोमीटर प्रवाह क्षेत्र में 130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हो जाता है । ऐसी कई नदियॉं हैं जो अपने बाढ़ क्षेत्र में सैकड़ो वर्ग किलोमीटर जमीन को प्रत्येक साल डुबोती हैं ।

पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल विहारी वाजपेयी जी ने जो स्वर्णिम योजना की शुभारंभ की थी, नदियों से नदियों को जोड़ने का जो काम शुभारंभ की थी ताकि नदियों का जल का समान वितरण कर बाढ़ की समस्या से निदान के साथ-साथ हर खेतों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाय ।

सभापति महोदय, बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94163 वर्ग किलोमीटर है जिसमें बिहार की कुल आबादी 89 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है और 11 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में बसती है । कुल क्षेत्रफल का 5694642 हेक्टेयर भूमि यानी 60.48 प्रतिशत भूमि पर कृषि होती है और कुल आबादी का 80 प्रतिशत लोग कृषि एवं इसके सहायक काम-धंधों पर निर्भर करते हैं ।

सभापति महोदय, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जहॉं राज्य के सिंचित खेती के विकल्पों को आगे लाकर ही किसानों के क्रय शक्ति को बढ़ाया जा सकता है । सभापति महोदय, इसके साथ-ही पूरे राज्य में जल प्रबंधन एवं जल आपूर्ति में अब घनात्मक बदलाव के साथ-साथ जल शक्ति का व्यवस्थित नियोजन भी किया गया है । पुराने पद्धतियों में बदलाव किया था जिसमें आज प्रौद्योगिकी बिहार की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है ।

सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एन0डी0ए0 सरकार ने सिंचाई के कुशल प्रबंधन पर सराहनीय कार्य किया है । जहॉं जल की सुलभता सीमित है, वहीं प्रति इकाई से अधिकतर खेतिहर पैदावार को बढ़ाया है । बिहार की कृषि योग्य असिंचित भूमि को सिंचित बनाने के लिए शताब्दी नलकूप योजना, ड्रिफ्ट इरीगेशन जैसी

अनेक जन कल्याणकारी योजनाएँ चलाकर पूरे बिहार में सिंचाई की स्थायी व्यवस्था प्रदान की है । कुंदर सिंचाई परियोजनाओं पर लगातार समीक्षा कर इस योजना को समाज के अंतिम यूनिट तक पहुँचाने का काम की है । मुख्यमंत्री जी के इन प्रयासों के लिए बिहार के किसान मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं ।

सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पूरे प्रदेश में 60.48 प्रतिशत किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए संकल्पित है और इस दिशा में कार्य भी शुरू हो चुका है । सभापति महोदय, हमारी सरकार का प्रयास है कि गंगा जल योजना के अंतिम चरण का कार्य इसी वर्ष अंत तक पूरा कर लिया जायेगा ताकि गया और राजगीर जैसे शहरों को पेयजल की समस्याओं से छुटकारा मिल सके ।

सभापति महोदय, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना पर काम चल रहा है जिसमें दरभंगा, मधुबनी जिले के लाखों किसान लाभान्वित होंगे । किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार संकल्पित है । सभापति महोदय, लोकतंत्र की जननी वैशाली प्रसिद्ध शांति स्तूप के निकट 2500 साल पुरानी हमारी सांस्कृतिक धरोहर अभिषेक पुष्कर्णी सरोवर जो सूख गई थी उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है । इसके लिए वैशाली शाखा के नहर से जल की आपूर्ति की जायेगी, यह काम 2021 में पूर्ण करने की सरकार का लक्ष्य है ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का ध्यान और साथ में मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि मैं विधान सभा के सदस्य के रूप में मोहिउद्दीननगर से आया हूँ, क्षेत्र भ्रमण के दरम्यान हमारे विधान सभा क्षेत्र के पटोरी प्रखंड और मोहिउद्दीननगर प्रखंड के अन्तर्गत बहुत सारे जो पंचायत हैं वे वर्षा और बाढ़ के दिनों में डूबे रहते हैं जिसमें राजस्व ग्राम लोदीपुर, सुल्तानपुर, छौराही, गरमुआ, उत्तरी धमौन, दक्षिणी धमौन, माधोपुर मोहनपुर तथा भदहिया के चौर जल निकासी हेतु 1969-70 के दौरान जो तत्कालीन सरकार थी, जल निकासी के लिए एक योजना पर काम कर रही थी जिससे हजारों एकड़ भूमि प्रभावित होती है लेकिन आज भी वह कार्य पूरा नहीं हो पाया है । अगर धमौन चौर से नहर की उड़ाही कराकर गंगा नदी में मिला दिया जाय तो वहाँ के किसानों के आय का स्त्रोत और खाद्यान्न उपज में काफी बढ़ोतरी होगी । इसलिए मैं सरकार का ध्यान विशेष रूप से इस विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ ।

धन्यवाद ।

सभापति (श्री अवध विहारी चौधरी) : माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार साहनी जी । माननीय सदस्य, आपको 6 मिनट समय आवंटित है ।

श्री अनिल कुमार साहनी : 10 मिनट था, सर ।

सभापति (श्री अवध विहारी चौधरी) : था, कटौती हो गया । माननीय सदस्य सुधाकर सिंह जी ने कुछ ज्यादा समय ले लिया था ।

श्री अनिल कुमार साहनी : सभापति महोदय, मैं आज पहली बार विधान सभा में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और बोलने से पहले अपने विधान सभा क्षेत्र के मतदाता मालिकों भाईयों-बहनों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें चुनकर यहाँ भेजा । अपने नेता, शोषितों-उपेक्षितों के नेता आदरणीय लालू यादव जी और बिहार के भविष्य तेजस्वी यादव जी के प्रति भी हम हार्दिक सम्मान और आभार व्यक्त करते हैं ।

महोदय, मैं आज विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ । आज जो यह प्रस्ताव आया है जल संसाधन विभाग द्वारा तो जल संसाधन विभाग का सिंचाई पर किस प्रकार से बिहार में खास करके हमारा बिहार जो उत्तर बिहार है और दक्षिण बिहार, दो भागों में बँटा है । एक तरफ सुखाड़ और एक तरफ बाढ़ । बाढ़ के कारण हमारा जो उत्तर बिहार के जिले हैं, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, गोपालगंज, छपरा, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, सहरसा, कोसी का क्षेत्र, पूर्णिया और जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ बाढ़ आती है इसका क्या कारण है कि बार-बार बाढ़ आती है और इसपर कोई कार्रवाई नहीं होती है । तटबंध बनते हैं और महोदय, तटबंध टूट जाते हैं । तटबंध इसीलिए टूटते हैं क्योंकि यहाँ मूसा बहुत बड़ा चीज है जो मूसा तटबंध को तोड़ने का काम करता है । इस राज्य में जहाँ मूसा तटबंध को तोड़ेगा और आपका यहाँ पर 40 अरब 74 करोड़ 38 लाख रू0 का यह बजट आयेगा तो इस राज्य का मूसा से जब यह बजट को बचा नहीं पायेंगे तो दुर्भाग्य है इस बिहार के लिए कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से ये बाढ़ और सुखाड़ से बचाया जायेगा । यह सिर्फ बोलने की बात है ।

मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि इस बाढ़ का कारण नेपाल है । मंत्री महोदय, आप दिल्ली में जाते हैं, प्रेस कांफ्रेंस करते हैं मगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री को इसपर बात करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करने के लिए आपने आजतक क्या पहल किया है ? आज तक आपने क्या पहल किया है कि कोसी बराबर दह जाता है, बराबर हमारा उत्तर बिहार दह जाता है, ये सारी व्यवस्थाएँ हैं । समय कम है, बहुत सारी चीज इसपर बोलने के लिए है, हमारा समय काट दिया गया है । महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूँ ।

महोदय, इसी के साथ जुड़ा हुआ है पशुपालन और मत्स्य पालन । मैं मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग से यह जानकारी लेना चाहता हूँ कि पशुपालन विभाग में केवल कागज पर टीकाकरण हो रहा है । कागज पर सिर्फ टीकाकरण हो रहा है । महोदय, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि खुरहा, मुँहपारा, एफ0एम0डी0, गलघोंटू एवं

लंगड़ी बीमारी सामान्य हो चुका है जिसका समय पर हमारे क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में भी टीकाकरण नहीं हो रहा है । सिर्फ कागज पर इसका गलत बिल बनाया जाता है । इसकी ओर भी माननीय मंत्री पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग का हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि आप इसपर ध्यान दें । खास करके मछुआ, जो हमारा फरक्का बाँध, मंत्री महोदय, सुनिए, यह बहुत बड़ी चीज है, फरक्का बराज जो बना, फरक्का बराज जब से बना है तब से परम्परागत मछली इस बिहार में आना खास करके उत्तर भारत में आना बंद हो गया है । परम्परागत मछली आना बंद हो गया ।

..क्रमशः..

टर्न-22/आजाद/02.03.2021

..... क्रमशः .....

श्री अनिल कुमार साहनी : आपको बता देना चाहता हूँ कि इसपर गंगा मुक्ति आन्दोलन और बागमती आन्दोलन चलाने वाले श्री अनिल प्रकाश जी माननीय मुख्यमंत्री जी से इसपर बातें की थी लेकिन इसपर कोई कार्रवाई नहीं की गई कि फरक्का बाँध को किस प्रकार से रोका जाय । मैं बता देना चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय कि जिस समय फरक्का बाँध बना था, उस समय वहां पर पानी की गहराई थी 75 फीट 1975 में और 2001 में उसी जगह का नापी लिया गया मार्च महीना में तो गहराई घटकर हो गयी 13 फीट, गाद और बालू से गंगा भरता जा रहा है .....

सभापति (श्री अवध बिहारी चौधरी) : माननीय सदस्य, आपका मात्र एक मिनट बचा हुआ है ।

श्री अनिल कुमार साहनी : हां सर, एक मिनट में अपनी बात को कंक्लूड कर देते हैं । पहली बार बोल रहे थे सर, मेरा समय कट गया । महोदय, फरक्का बाँध के कारण सभी लोगों की समस्या है । खासकर के मछुआरा वर्ग इसके कारण भूखमरी के कगार पर है और माननीय मंत्री, पशुपालन एवं मत्स्य से मछुआरों के संबंध में कुछ समस्यायें हैं उसको उठाना चाहता हूँ । माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 2014 में स्पष्ट रूप से घोषणा किया था जब लालू यादव जी ने मछली को फ्री किया था ताड़ी और मछली को तो उसी के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था कि एक रूपया के टोकन मनी पर बन्दोबस्ती किया जायेगा जलकरों को परम्परागत मछुआरों के साथ । लेकिन आज तक वह बन्दोबस्ती कथनी और करनी में अन्तर ही होकर रह गया । अब तक 6 सालों में एक रूपया टोकन मनी पर बन्दोबस्ती नहीं किया गया ......

सभापति (श्री अवध बिहारी चौधरी) : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें ।

श्री अनिल कुमार साहनी : महोदय, एक मिनट । मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय मछुआ आयोग का गठन कब करेंगे, सैरात रिमिशन कमेटी का गठन कब करेंगे, मत्स्य बीज विकास निगम का गठन कब करेंगे, मछुआरों को इनश्योरेंस कब देंगे, मछुआरा आवास योजना कब बनायेंगे, माननीय मंत्री जी द्वारा जो घोषित किया गया है उसको कब पूरा करेंगे ? इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि सकारात्मक रूप से जो हमारे मछुआ समाज के लोग हैं उनको जो है आप लाभ पहुँचावें । आने वाले दिनों में इन्हें जो हैं एक रूपया टोकनी मनी पर जलकर का बन्दोबस्ती करावें ।

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी) : माननीय सदस्य, अब आप अपना स्थान ग्रहण करें । माननीय श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद । आपका समय मात्र 4 मिनट है ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : सभापति महोदय, मैं एक विशेष सूचना पर खड़ा हूँ ।

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी) : कहा जाय ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : सभापति महोदय, सूचना यह है कि बिहटा से लेकर के कोईलवर और कोईलवर से लेकर के छपरा तक करीब एक वर्ष से महाजाम की स्थिति बनी हुई है । अभी किसी तरह हम गिरते पड़ते विधान सभा में पहुँचे हैं कई देहाती क्षेत्रों से घुमते हुए । (व्यवधान)

एक समस्या है, जिसके बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि बिहटा मोड़ पर अरवल से लेकर के, औरंगाबाद से लेकर के जहानाबाद कई जिलों की गाड़ियां वहां आ रही है । सरकार निश्चित रूप से व्यवस्था करे ताकि वहां पर जाम की स्थिति समाप्त हो अन्यथा बहुत द :खद स्थिति होगी । स्थिति यहां तक हो गई है कि कृषि मंत्री जी को 28 तारीख को वहां पर कृषकों का आयोजन था और उसका उद्घाटन करना था, कोईलवर से उन्होंने जाम से वहां ....

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी) : माननीय सदस्य, आपने सदन के माध्यम से सरकार को सूचित किया, सरकार आपकी सूचना ग्रहण कर रही है । अब आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : धन्यवाद ।

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी) : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण किया जाय ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, हमारे सचेतक महोदय हैं, माननीय मंत्री जी भी हैं और हमारे माननीया उप मुख्यमंत्री जी भी हैं । सरकार कम से कम कहे कि हमने सूचना ग्रहण किया ।

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी) : सैयद रूकनुद्दीन अहमद साहेब, अपनी बात को रखें। आपका समय बहुत ही कम है ।

श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद : सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए उठा हूँ । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ ।

सबसे पहले मैं अपने बायसी विधान क्षेत्र के लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे यहां आने का मौका दिया । महोदय, सीमांचल इलाका हर साल बाढ़ की त्रासदी को झेलता है । यहां परमार महानन्दा, पनार कनकई दास इत्यादि नदियां बहती है जिससे हर साल भीष्ण कटाव होता है । इन सारी नदियों का बहाव सबसे ज्यादा बायसी, अमौर, कोचाधामन बहादुरगंज को प्रभावित करता है । नदियों में भीषण कटाव के कारण इन क्षेत्रों में बड़े-बड़े गांव नदियों से कटकर विलिन हो गये हैं । कटाव पीड़ित परिवार विस्थापित हो चुके हैं । विस्थापित परिवारों को सड़कों पर जीवन बसर करना पड़ रहा है । विस्थापित परिवारों के लिए सरकार अभी तक कोई पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करायी है जो बड़े ही चिन्ता और खेद का विषय है । वर्ष 2017 में आयी भीषण बाढ़ से ही पूर्णिया जिला के बायसी विधान सभा क्षेत्र के ताराबाड़ी, चनकी, हाथीबंधा, नवाबगंज, मथुरापुर, खपड़ा, हरिनतोल, बनगांवा, गोटफोर खुटिया, बैरिया, पहाड़िया जैसे गांव नदी में कटकर विलिन हो गये हैं । अब तक इन गांवों में कटाव निरोधक कार्य नहीं कराये गये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि इन गांवों में शीघ्राशीघ्र कटाव निरोधक कार्य कराया जाय । इन गांवों से गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़क जो कई पंचायतों को जोड़ती है । इनका भी स्तित्व अब खतरे में है। सरकार इन गांवों में शीघ्र कटाव निरोधक कार्य कराया जाना चाहिए एवं कटाव पीड़ित विस्थापित परिवारों को पुनर्वास की व्यवस्था शीघ्र करानी चाहिए ताकि इन लोगों का जीवन-बसर हो सके । इसी प्रकार अमौर विधान सभा क्षेत्र के बैसा बिरजान टोला, काशीबाड़ी, सीमलबाड़ी, तालबाड़ी, गौरिया अधान और बहादुरगंज के पत्थरघटी की यही स्थिति है । मैं माननीय मंत्री महोदय से यह मांग करूंगा कि इन गांवों में शीघ्र कटाव निरोधक कार्य कराया जाय ताकि इनकी दशा और दिशा दोनों को बचाया जा सके । बोलने का आपने मुझे मौका दिया, टाईम है . ....

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी) : अब स्थान ग्रहण किया जाय । श्री अरूण सिंह जी, सी0पी0आई0एम0एल0 ।

श्री अख्तरूल ईमान : महोदय, 5 मिनट का समय था ।

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी) : उनको 4 मिनट का समय था और उनका समय हो गया है।

श्री अरूण सिंह : सभापति महोदय,

श्री अख्तरूल ईमान : सभापति महोदय, सीमांचल में जो कटाव हुआ है

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी) : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें । इनका सुन लिया जाय ।

श्री अख्तरूल ईमान : सभापति महोदय, मामला यह है कि वहां पर भीषण कटाव हुआ है और कटाव जारी है । अभी सदन में बात चल रही है कि लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई हो रही है

लेकिन हमारे क्षेत्र में जीरो है, सिंचाई नहीं हो रही है । हमारे यहां सबसे ज्यादा काम है कटाव निरोधक । हजारों परिवार हर साल विस्थापित हो रहे हैं । जितनी भी नदियां बह रही हैं किशनगंज में और पूर्णिया में कोशी के किनारे से निकलती है और सारा समाहित हो जाती है अमौर, बैसा और बायसी में और नतीजा यह होता है कि तेज धारा और घनी नदियों के कारण वहां हजारों परिवार विस्थापित हो गये हैं, उसपर माननीय मंत्री जी से ... ..

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी) : माननीय सदस्य, अब आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री अख्तरूल ईमान : महोदय, हम यही तबज्जो दिलाना चाह रहे हैं । महोदय, चूँकि वहां पर पीड़ित लोग हैं, इस बार भी अगर कटाव हो गया तो हमलोग क्षेत्र में जाने लायक नहीं रहेंगे हुजूर ।

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी) : माननीय सदस्य श्री अरूण सिंह जी । आपका समय आवंटित है मात्र 9 मिनट ।

श्री अरूण सिंह : सभापति महोदय, जल संसाधन विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ । सरकार का जो संकल्प है कि हर घर को हम नल से पानी पहुँचायेंगे और हर खेत को हम पानी देंगे । लेकिन उतना ही विडम्बना है इस राज्य का कि पूरे बिहार का आधा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है और आधा हिस्सा सुखाड़ से प्रभावित है । सरकार हमेशा कहती है कि हम हर संकट को अवसर में बदलने की बात कहती है । हमने देखा है कि कोरोना को जिस तरह से अवसर में बदला गया कि कल हमारे विधायक साथियों पर लाठी बरसाई गयी । उसी तरह से हम देख रहे हैं कि बाढ़ नियंत्रण के नाम पर, बाढ़ प्रबंधन के नाम पर जब भी हम सुनते हैं तो बॉध की ऊँचाई को बढ़ा दिया जाय और सुखाड़ के नाम पर हम सुन रहे हैं कि डिजल की सब्सिडी बढ़ा दी जाय, उसकी रकम बढ़ा दी जाय । इसके अलावे हम नहीं समझते हैं कि सरकार दूसरा कोई काम कर रही है । हम जानते हैं महोदय वृहद सिंचाई परियाजना का एकमात्र उद्देश्य है कि संकट के समय हम खेतों तक पानी पहुँचायें ।

...... क्रमशः .....

टर्न-23/शंभु/02.03.21

श्री अरूण सिंह : क्रमशः लेकिन हम देख रहे हैं कि इस तरह की तीन परियोजनाएं हमारे बिहार में काम कर रही है- एक है कोशी परियोजना । कोशी परियोजना की उपलब्धि में कहीं भी उसमें डैम नहीं है । उसमें पानी आता है और बह जाता है । इसलिए मैं देख रहा हूँ कि कभी भी संकट के समय पानी नदी नहीं दे पाती है । इस तरह से यह परियोजना एक तरह से भष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है । इसी तरह से गंडक परियोजना, गंडक परियोजना पर तो करीब 10 सालों से यहां के किसान विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि

इससे तबाही होगी, हमारी खेती बर्बाद होगी, हमारे यहां जल प्रलय होगा, लेकिन इसके बावजूद, सरकार के निदेशन के बावजूद भी कि इसकी एक रिव्यू कमिटी बनायी जायेगी, लेकिन रिव्यू कमिटी के बिना रिपोर्ट के यह कार्य फिर से चलाने की कोशिश की जा रही है । महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि किसके दबाव में, किस कारण से यह परियोजना फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है । महोदय, इसमें भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार है । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस सोन प्रणाली की बात चल रही है, यह सोन प्रणाली 1874 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिहार को सुपुर्द किया था, जो अविभाजित बिहार था, लेकिन यह प्रणाली आज पूरी तरह से मृतप्राय पड़ी हुई है । हम उस जगह से आते हैं जहां से सोन नदियां निकलती है रोहतास जिला- ये सोन प्रणाली का रोहतास जिला में भी पटवन कराने की क्षमता कम हो गयी है, अंतिम छोड़ तक पानी नहीं पहुंचा पाती है । बहुत पहले से यह मांग उठ रही है, इस मामले में बहुत आंदोलन हुए हैं बिहार में कि कदवन में अगर जलाशय का निर्माण किया जाय तो शायद हम इस सोन प्रणाली को जो 150 वर्ष पुरानी हमारी प्रणाली है, जो बिहार को बैठाकर खिलाने की ताकत इस इलाके की है उसको बर्बाद होने से बचाया जा सकता है, लेकिन इस सोन प्रणाली को अभी तक इस बजटीय प्रावधान में हमने देखा, मुख्यमंत्री जी पहले वहां जाकर भ्रमण भी कर आये, शिनाख्त भी कर आये कि कदवन के मटिहानी में इस जलाशय का निर्माण किया जायेगा, लेकिन इस बजट प्रावधान में एक शब्द भी रहस्यमय ढंग से चुप्पी साध ली गयी और इस रहस्यमय ढंग से चुप्पी का मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं । इतनी बड़ी परियोजना, जिस परियोजना के बल पर हम बिहार को बैठाकर खिलाने की ताकत रखते हैं । इसपर सरकार क्यों नहीं बजटीय प्रावधान कर रही है ? इसपर बजटीय प्रावधान करना चाहिए तब जाकर हम बिहार के विकास की बात सोच सकते हैं । अगर यह सरकार सही मायने में विकासोन्मुखी है, विकास के लिए तत्पर है, विकास के लिए सबकुछ करती है मरती है, जीती है तो बिहार के विकास का हम समझते हैं कि सोन नहर सबसे बड़ी परियोजना है और सारे काम रोककर भी इस परियोजना को चालू करना पड़े तो पैसा खर्च करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन एक पैसा सरकार ने इस परियोजना में खर्च नहीं किया है । पिछले दिनों इसी सदन में जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था तो सरकार का उत्तर था कि हम तीन महीने के अंदर डी0पी0आर0 बना देंगे, लेकिन इतने दिन हो गये डी0पी0आर0 नहीं बन पा रहा है । इसलिए महोदय, इस समस्या पर मतलब अति महत्वपूर्ण समस्या है इसपर ध्यान देना चाहिए । मैं इसमें जो बजटीय प्रावधान है उस बजटीय प्रावधान पर मैं कहना चाहता हूँ जो सोन नहर हिस्से से संबंधित है कि इसको बढ़ाकर कम से कम 6 हजार करोड़ रूपया किया जाय ताकि सोन नहर का कदवन का निर्माण किया जा सके । यह कोशिश सरकार को करनी चाहिए । मध्यम सिंचाई

परियोजना– मध्यम सिंचाई परियोजना में हम देख रहे हैं कि 21481 हे0 जमीन इससे सिंचित होती है । लेकिन हम देख रहे हैं कि एक मात्र कैमूर के दुर्गावती जलाशय को छोड़ दिया जाय तो यह मध्यम सिंचाई परियोजना– पूरी परियोजना जमुई और लखीसराय जिले में चल रही है और बिहार के किसी कोने में इस परियोजना का कोई भी काम नहीं चल रहा है । अब इसका मतलब मैं नहीं समझ पाता कि ऐसा क्यों ? क्यों नहीं अन्य जिलों में जहानाबाद हमेशा सुखाड़ से प्रभावित रहता है, गया प्रभावित रहता है बहुत सारे वहां स्रोत हैं जहां मध्यम सिंचाई परियोजना स्थापित किया जा सकता है । वहां क्यों नहीं ऐसा किया जा रहा है, क्यों दो जिले में पूरी परियोजना को सिमटाकर रखा गया है । इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ ।

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी) : माननीय सदस्य, अब आपका समय केवल 2 मिनट बचा है ।

श्री अरूण सिंह : इसमें जो मांग हमारा बनता है उसको मैं पढ़ रहा हूँ । जल संसाधन के लिए व्यापक उपाय किया जाय, तमाम जल स्रोतों का संरक्षण किया जाय, सार्वजनिक आहरों, पोखरों को दुरूस्त किया जाय, बृहत्तर सिंचाई योजनाओं को तत्काल हाथ में लिया जाय, लेकिन कदवन जैसे डैम एवं अन्य संभावित परियोजनाओं को अपनाया जाय इसके लिए पर्याप्त वित्तीय प्रबंधन किया जाय । सोन नहर आधुनिकीकरण को शीघ्र हाथ में लिया जाय और उसका देखरेख प्राइवेट कमिटियों को नहीं सौंपा जाय । नहरों की देखरेख के लिए व्यापक तौर पर कर्मचारियों, इंजीनियरों, मेटों, तकनीकी सहायकों की नियुक्तियां की जाय । महोदय, आजकल एक और प्रचलन है ।

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी) : महोदय, अब आपका समय समाप्त हो चुका है अन्य सदस्य को भी बोलना है । आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री अरूण सिंह : नहरों की वितरणी को जो प्राइवेट हाथों में देने की कोशिश चल रही है इसको समाप्त किया जाय और नहरों की वितरणी को सरकार अपने हाथ में ले तब जाकर जल संसाधन सिंचाई विभाग और हमारी कृषि सुरक्षित हो सकती है ।

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी) : माननीय सदस्य, श्री राजकुमार सिंह, आपको मात्र 1 मिनट समय आवंटित है और 1 मिनट में ही आपको जो बजट पर कहना है उसपर आप अपनी बात को रखें ।

श्री राजकुमार सिंह : माननीय सभापति महोदय, बोलने से पहले एक आग्रह करना चाहूंगा कि 1 मिनट का समय शायद मेरी सदस्य संख्या के आधार पर मुझे दिया गया है, किन्तु यह बिलकुल ही नाकाफी है ।

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी) : आप अपनी बात बजट पर बोलिये । आप अपना समय बर्बाद नहीं करे इसलिए कि मात्र 1 मिनट ही आपको आवंटित है ।

श्री राजकुमार सिंह : महोदय, थोड़ा अवसर और दिया जाय क्योंकि मैं एक सदस्य जरूर हूँ, लेकिन मैं बिहार की लगभग 24 लाख मतदाताओं की एक मात्र आवाज हूँ इस सदन में इसलिए मुझे कम से कम 1 मिनट और दिया जाय ।

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी) : आप भूमिका में नहीं जाएं, अपनी बात को रखें ।

श्री राजकुमार सिंह : माननीय सभापति महोदय, जल संसाधन विभाग के संबंध में जो कटौती प्रस्ताव दिया गया है यहां पर विपक्ष के द्वारा मैं न तो इसके पक्ष में बोलकर न विपक्ष में बोलकर किसी स्कूली वाद-विवाद प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ । मैं इस अवसर का प्रयोग अपने क्षेत्र मटिहानी विधान सभा क्षेत्र जो कि बाढ़ के कारण हमेशा, हर साल आपदाग्रस्त होता है उसकी समस्या की ओर सरकार का और माननीय मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ । मटिहानी विधान सभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो कि गंगा के दोनों किनारों पर बसा हुआ है और इसकी बहुत बड़ी आबादी है और हर साल ये आबादी बाढ़ की त्रासदी को झेलती है ।

क्रमशः

टर्न-24/ज्योति/02-03-2021

क्रमशः

श्री राज कुमार सिंह : आपको जानकर काफी अफसोस होगा कि कटाव के कारण विगत 30 सालों से 2 हजार परिवार आज भी गुप्ता लखमिनियां बांध पर बसे हुए हैं और उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । गुप्ता लखमिनियॉं एकमात्र एकमात्र ऐसा बांध है, तटबंध है जो बेगुसराय जिले को जो कि एक औद्योगिक राजधानी है बिहार की और मुख्यालय भी है उसकी सुरक्षा के लिए एक मात्र बांध है गुप्ता लखमियॉं बांध ।

सभापति (श्री अवध बिहारी चौधरी): अब आप समाप्त करें, आपने एक मिनट ज्यादा बोल लिया इसलिए आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री राज कुमारसिंह : सर मुझे थोड़ा सा बोलने का अवसर दिया जाय, इसलिए मेरा सुझाव होगा।

सभापति (श्री अवध बिहारी चौधरी): अब श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी जी ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : सभापति महोदय, जल संसाधन विभाग पर हिन्दुस्तानी आवास मोर्चा के प्रतिनिधि के तौर पर मैं बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । जल संसाधन विभाग एक ऐसा विभाग है जहॉं बिहार की आबादी का बहुसंख्यक गांव में बसते हैं और गांव में बसने के कारण यहॉं के बहुत सारे किसान बहुत बड़े नहीं हैं । छोटे और मध्यम स्तर के किसान हैं जिसकी सिंचाई के लिए सरकार ने चूँकि मेरा समय कम है, बहुत कम समय अपने बजट पर राय रखूंगा और अपने क्षेत्र की समस्या पर रखूंगा और कहना चाहते हैं कि सरकार ने छोटे छोटे किसानों के लिए लघु जल संसाधन

विभाग की ओर से जो जल जीवन हरियाली के तहत हर खेत में पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है, वह बहुत कारगर है । साथ ही साथ मेरा क्षेत्र मैदानी क्षेत्र होने के साथ साथ ही पहाड़ों और वनों से आच्छादित है इसलिए सिंचाई की भी बहुत सारी असीम संभावनाएं हैं । हमारे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2008 में जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कुंड सिंचाई परियोजना, 2008 में घोषणा की गयी थी और 2010 में संचालित की गयी है । 50 करोड़ की राशि से बढ़ा कर उस परियोजना को 70 करोड़ का किया गया है लेकिन जो संवेदक हैं विजेता कंसट्रक्शन कंपनी वह पेटी कौन्ट्रैक्टर को अपना ठीका दिए और वह दोनों आपस में लड़कर उस परियोजना का बंदरबाट कर रहे हैं । काम प्रारम्भ नहीं कराया जा रहा है और जिसके कारण है कि वह समय बढ़ता जा रहा है, राशि भी बढ़ती जा रही है । महोदय, आपके माध्यम से माननीय जल संसाधन मंत्री से निवेदन करेंगे कि इन विजेताओं की समस्या का आपस में निदान करवा कर काम शीघ्र करायें ।

सभापति (श्री अवध बिहारी चौधरी) : माननीय सदस्य आपका समय सीमा समाप्त हुआ ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : महोदय, एक मिनट सर, खाली इसको पूरा कर लेते हैं सर । महोदय, साथ ही साथ संवेदकों की लड़ाई को जल्द से जल्द निपटारा कराकर कुंड सिंचाई परियोजना को लागू करवाने का काम करेंगे । एकमात्र कैलाश डैम सिंचाई परियोजना है । उस पर माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि वह बालाडीह गांव से मात्र उसका पानी दरखा तक जाता है जबकि वह बालाडीह गांव से होते हुए दरखा होते हुए बालडा मोड़ और कईआर तक उसको जाना है नहर की स्थिति सुदृढ करवा दें और पानी की समस्या को समाप्त करने का काम करेंगे । बहुत बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री अवध बिहारी चौधरी) : माननीय सदस्य श्री मिश्री लाल यादव जी 3 मिनट ।

श्री मिश्री लाल यादव : माननीय सभापति महोदय, आपके प्रति, अलीनगर जनता के प्रति और वी. आई.पी. के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री श्री मुकेश सहनी जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ । महोदय, आज बिहार में एन.डी.ए. की सरकार जिसका मुखिया मान्यवर नीतीश कुमार जी हैं और उप मुख्यमंत्री तार किशोर जी हैं, उनके नेतृत्व में चहुमुखी विकास हो रहा है । मैं सरकार के बजट कें पक्ष में खड़ा हूँ । जहॉ तक पशु मत्स्य संसाधन विभाग का सवाल है उस में मैं समझता हूँ कि जो पहले मछली का उत्पादन हमारे राज्य में बहुत कम हुआ करता था और पूरा का पूरे तौर पर दूसरे राज्यों से मछली का निर्यात कराया जाता था । अब सदन को सुन कर बड़ी खुशी होगी कि राज्य में मछली का औसत और उसका वार्षिक उत्पादन 2.88 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर 6.41 लाख मैट्रिक टन हो गया है और इससे पूर्व बिहार में अन्य राज्यों से मछली का आयात 2 से 3 लाख मैट्रिक टन था जो घट कर मात्र 0.4 लाख मैट्रिक

टन रह गया है । मान्यवर, सभापति महोदय, हमें लगता है जो इन पॉच वर्षो में 0.4 लाख टन रह गया है अब बिहार इस स्थिति में है कि बिहार की मछली दूसरे राज्यों में भी जायेगी। इतना उत्पादन हमारा बढ़ रहा है । जहॉ तक पशु का सवाल है । पशु के सवाल पर भी बिहार सरकार कई ऐसे कार्यों को कर रही है । पहले प्रखंड स्तर पर एक अस्पताल हुआ करता था और अब सरकार ने निर्णय लिया है कि हम 8 से 10 पंचायत पर एक पशु अस्पताल का निर्माण करेंगे, यह उनका चहुमुखी विकास की ओर ध्यान है । अब मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले जल संसाधन के सवाल पर इधर विपक्ष की ओर से कहा गया कि कटौती के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री जो संजय झा जी हैं, उनको पैसा खर्च करने में तत्परता नहीं है । महोदय, पिछली बार अलीनगर विधान सभा क्षेत्र से चुनाव हार गया था और उस इलाके का बांध टूटा था लेकिन जब ये मंत्री बने तो इस बार जो बाढ़ आयी पिछले साल में तो संजय झा के नेतृत्व में और बिहार सरकार के नेतृत्व में बांध को टूटने नहीं दिया । रात रात भर बिजली जला कर बांध का निर्माण कराया । मैं मान्यवर मंत्री जी से कहना चाहता हूॅ कि एक उसी इलाके में घनश्यामपुर में एतबार गांव है और दो तटबंध के बीच में है और बाढ़ में घिर जाता है और घिरने के बाद उसमें यातायात का साधन बंद हो जाता है मैं मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि पुलनुमा सड़क का निर्माण किया जाय और दूसरा एक भेड़ियाराही गांव हैं जो नदी से दोनों तरफ घिरा हुआ है । बाढ़ के जमाने में उससे आना जाना बंद हो जाता है वहॉ भेड़ियाराही मे पुल का निर्माण कराया जाय । मैं इन्हीं शब्दों के साथ बिहार के चहुमुखी विकास करने के लिए बिहार सरकार को बधाई देना चाहते हैं ।

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी): आप स्थान ग्रहण करें । डा0 सत्येन्द्र यादव एक मिनट सी.पी. आई. एम ।

डा0 सत्येन्द्र यादव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि की समस्याओं के समाधान करने के लिए बजट प्रस्ताव में चर्चा की है कि हर खेत तक पानी पहुंचायेंगे । बिहार के अंदर दो प्रमुख समस्यायें हें कृषि के अंदर एक जल जमाव की और दूसरी सूखे की । सारन जिले के अंदर जल जमाव की समस्या गंभीर है । जलालपुर प्रखंड के अन्तर्गत तेल नदी के कारण दर्जनों पंचायत जल मग्न रहते हैं जिसके चलते गेहूॅ की खेती नहीं हो पाती, धान की खेती हम नहीं कर पाते । उसी तरह से मशरख के अंदर घोघरडीहा और परिहारा चौर में मढ़ौरा प्रखंड के अंतर्गत ताल पुरैना एवं एकमा प्रखंड के अंदर धूरदेव चौर के अंदर जल जमाव की समस्या के चलते हजारों एकड़ जमीन पर खेती नहीं हो पा रही है । हम जल संसाधन विभाग से मांग करना चाहते हैं कि जल जमाव की समस्या का त्वरित समाधान निकाला जाय । दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूॅ कि सारन

जिला में ही सारन प्रमंडल के अंदर गण्डक नहर बनी हुई है । आज कई वर्षो से गंडक नहर के निर्माण की बात चल रही है । काम चल रहा है । एक तरफ निर्माण हो रहा है दूसरी तरफ पी.सी.सी. उखड़ रहा है । अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं है । सारन जिला के अंदर मात्र 150 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है। सारन जिला के अंदर 2000 क्यूसेक पानी की जरुरत है हम सरकार से कहना चाहते हैं कि बिहार की जो सरकार है वो जल संसाधन विभाग एक तरफ जल जमाव की समस्या का समाधान नहीं करता और दूसरी तरफ सारन के गंडक नहर में पानी नहीं देती । सरयू नदी और गंडक नदी के कारण बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हो रहे हैं उनके बचाव का इंतजाम किया जाय और मैं कहना चाहता हूँ कि जल संसाधन विभाग में जो बजट का उपबंध है उसमें बड़े पैमाने पर बंदरबाट हो रहा है ।

टर्न-25/अभिनीत/पुलकित/02.03.2021

सभापति (श्री अवध बिहारी चौधरी): अब श्री भीम कुमार । आपका 6 मिनट समय है ।

श्री भीम कुमार: सभापति महोदय, सरकार द्वारा जो जल संसाधन विभाग की मांग प्रस्तुत की गयी है और उस पर जो कटौती प्रस्ताव सदन में लाया गया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, मैं अपने जिला की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ । वर्ष 1994 में हमीदनगर बैराज का शिलान्यास हुआ था और उसमें काम भी हुआ लेकिन आज कि स्थिति में वहां काम बिल्कुल बंद है । हमीदनगर बैराज के बन जाने से पूरे मगध जोन के खेतों को पानी मिलेगा । औरंगाबाद जिला ही नहीं जहानाबाद, अरवल तमाम इन जिलों में, पटना उसको बन जाने से सारे खेतों को पानी मिलेगा और उसमें काम भी हो चुका है । 2005 में, 1994 में 80 करोड़ का प्रोजेक्ट यह था और 2005 में सरकार ने उसको 206 करोड़ रूपया दिया लेकिन काम जस का तस है, उसमें काफी लूट हुई, उसमें कोई काम नहीं हुआ और बैराज बिल्कुल बंद है इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहेंगे और माननीय मंत्रीजी भी सदन में हैं कि इसकी जांच करायें और दोषी पदाधिकारी और संवेदक पर, ठेकेदार पर कार्रवाई करें, क्योंकि सरकार का काफी 300 करोड़ से ज्यादा रुपया उस पर लग गया है और काम जस का तस है । कोई माइनर खुदाई भी वहां नहीं हुई है, किसानों को जमीन का पैसा भी नहीं मिला है, विस्थापित लोगों को दूसरे जगह जमीन देना था कोई जमीन नहीं दिया गया है और न ही उनको जमीन के पैसे का भुगतान किया गया है, इसलिए महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से, मंत्रीजी से मांग करेंगे कि उसकी जांच करायें ।

हमारे क्षेत्र में जो मूल सोन कैनाल है, जो अंग्रेजों का बनायी हुई है । इसकी स्थिति काफी जर्जर है और इस कैनाल से हसपुरा प्रखंड में माली माइनर है जो अंग्रेजों

का ही बनाया हुआ है उसकी स्थिति भी काफी जर्जर है और यह 32 किलोमीटर लंबा है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि इसको दिखवाकर इसका जीर्णोद्धार करवाया जाय, क्योंकि यह इलाका धान का कटोरा है । यहां सिंचाई में काफी असुविधा हो रही है, इसका उड़ाहीकरण करा देने से, गया जिला तक यहां से पानी जाता है, इसलिए इस कार्य को कराना अति आवश्यक है ।

दूसरा, गोह प्रखंड अंतर्गत टेकारी सोन हाई लेवल कैनाल है, यह नहर पटना हाई लेवल कैनाल बारून से निकली हुई है और इसकी स्थिति भी काफी दयनीय है । इसमें काफी पानी जाता है, पानी की कोई कमी नहीं है लेकिन जहां-तहां इसकी स्थिति खराब हो गयी है, अवैध कल्वर्ट आउट लेट बैठा हुआ है और पानी की बर्बादी हो रही है । गया जिला के किसानों तक पानी नहीं जा पा रहा है, गोह तक जाते-जाते उसमें दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से मांग करेंगे कि इसको दिखवाकर इसको बनवाने का कष्ट करें । सोन उच्च कैनाल टेकारी जो नहर है, दुलारचक माइनर कैथी से औंकरी तक जीर्णशीर्ण अवस्था में है । हम आपके माध्यम से मांग करेंगे कि इसकी जांच कराकर इसका जीर्णोद्धार किया जाय ।

सभापति महोदय, मीरपुर माइनर जो थाल है वहां पर रिटर्निंग वॉल नहीं है, इसलिए बराबर वहां मिट्टी की कटाई हो जाती है, फॉल टूट जाता है और पानी बेकार में खेत में जाकर के किसान की फसलों को बर्बाद कर देता है, इसलिए आपके माध्यम से हम मांग करेंगे कि इसको बनवाया जाय । महोदय, मल्हद से सोसना तक और द्ववाल-सिंदुआरी जो गया जिला में पड़ता है, उसमें लगभग जो सर्विस रोड टेकारी कैनाल पर बनाया गया है, सोन उच्च स्तरीय टेकारी कैनाल पर वह 3 किलोमीटर रोड नहीं बना है । महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा और जो भी काम यहां पर हुआ है उसकी गुणवत्ता बहुत खराब है । एक तरफ रोड बनती है और दूसरी तरफ खराब होती है, यह बहुत ही उपयोगी रोड है । महोदय, सिंचाई विभाग की जो सर्विस रोड है, 3 किलोमीटर सड़क बिल्कुल जीर्णशीर्ण अवस्था में है, इसलिए इसको बनवाया जाय ।

सभापति(श्री अवध विहारी चौधरी): माननीय सदस्य, श्री भीम कुमार जी, आपका समय समाप्त हुआ, स्थान ग्रहण करें । श्री सूर्यकांत पासवान, सी0पी0आइ0 एक मिनट ।

श्री सूर्यकांत पासवान: सभापति महोदय, हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है । यहां जल प्रबंधन नहीं होने के कारण बाढ़ और सुखाड़ दोनों का दंश किसानों को झेलना पड़ता है । महोदय, हमारा जिला बेगूसराय इसका उदाहरण है । महोदय, यहां 90 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर रहते हैं और इस बार भारी बारिश के कारण हमारे क्षेत्र के गढ़पुरा, बखरी, नावकोठी के तमाम प्रखंडों में सैकड़ों लोगों की पहले खरीफ की फसल नष्ट हुई फिर रबी की बुआई नहीं

हो पाई । महोदय, मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री से मांग करता हूं कि सर्वे कराकर के नई नहर का निर्माण एवं पुरानी नहर की उड़ाही के साथ ही किसानों की फसल की जो क्षति हुई है उसकी भरपाई की जाय । महोदय, एशिया महादेश का सबसे बड़ा झील, काबर झील पक्षी बिहार के नाम से जाना जाता है लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण उस पर खतरा मंडरा रहा है । महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि काबर झील को पर्यटक स्थल बनाकर विकसित किया जाय । महोदय, सिंचाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे बिहार में स्टेट टयूवबेल का जीर्णोद्धार करने का काम किया है लेकिन उसका नाला निर्माण एवं पाईप के द्वारा सिंचाई करवाने की कोई व्यवस्था आजतक नहीं की गयी है । महोदय, हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि बिहार के अंदर बाढ़ और सुखाड़ का स्थायी निदान हो ।

सभापति(श्री अवध विहारी चौधरी): आपका समय समाप्त हुआ, अपना स्थान ग्रहण करें । श्रीमती कविता देवी, आपका समय चार मिनट ।

श्रीमती कविता देवी: माननीय सभापति महोदय, मुझे पशु एवं मत्स्य संसाधन के बजट 2021-22 के समर्थन में बोलने के लिए जो समय दिया गया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं । माननीय सभापति महोदय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने एवं ग्रामीण स्वरोजगार के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने पशुपालकों एवं मत्स्यपालकों को होने वाली आर्थिक क्षति से बचाने एवं उनके विकास के लिये, कई रोजगारपरक योजनाएं शुरू की हैं । इसके तहत एक लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को जीविका के माध्यम से अनुदानित दर पर चूजा वितरण एवं नि:शुल्क रूप से बकरी वितरण का काम किया गया है । माननीय सभापति महोदय, राज्य में सभी पशुओं की पहचान हेतु ईयर टैगिंग का कार्य किया जा रहा है । इसके तहत लाखों पशुओं का ईयर टैगिंग माह दिसंबर, 2020 तक हमारी सरकार द्वारा कराया गया है । इससे सभी पशुओं का टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान तथा पशुओं के लिये चलाये जा रहे विभिन्न योजनाओं का लाभ पशुपालकों को मिलेगा । माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार द्वारा राज्य में पशुओं की नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत राष्टीय्र डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से 84.2748 करोड़ की लागत से मरंगा, पूर्णिया में नये सीमन स्टेशन स्थापित किये जा रहे हैं, साथ ही कृत्रिम गर्भाधान के विस्तार के लिए 780 पशुधन विकास केन्द्रों की स्थापना पी0पी0पी0 मोड पर स्थापित की गई है । माननीय सभापति महोदय, राज्य के दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कॉम्फेड के माध्यम से पशुपालकों को सहयोग दिया जा रहा है तथा दुग्ध क्षमता को बढ़ाने के उद्‌देश्य से राज्य में दस परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए ...(क्रमश:)

टर्न-26/हेमन्त-धिरेन्द्र/02.03.2021

...क्रमशः...

श्रीमती कविता देवी : हमारी सरकार द्वारा 234.75 करोड़ रु0 की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है । माननीय सभापति महोदय, मत्स्य उत्पादन में बिहार देश का चौथा राज्य हो गया है तथा राज्य में बायो फ्लॉक तकनीक से मत्स्य पालन की योजना शुरू की गयी है । जिसके तहत अभी तक कुल 194 बायो फ्लॉक यूनिट स्थापित की गयी हैं । माननीय सभापति महोदय, राज्य में कृषि रोड मैप के कारण दूध, मछली एवं अण्डा के उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है । राज्य में दूध का औसत वार्षिक उत्पादन 57.67 टन से बढ़कर 104.94 लाख मीट्रिक टन हो गया है, जिसके कारण राज्य में 50 प्रतिशत दूध का आयात घट गया है, जिससे पशुपालकों को काफी लाभ हुआ है । माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं योजनाओं के तहत राज्य के अधिक से अधिक गांवों तक दुग्ध सहकारी क्षेत्र का विस्तार कर गांवों में ही दुग्ध उत्पादकों को उनके दूध के विक्रय एवं पशुपालन हेतु व्यवस्था करना है, जिससे पशुपालकों का अधिक लाभ हो । माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार दुग्ध व्यवसाय से जुड़े किसानों, बेरोजगारों, युवक-युवतियों को समग्र गव्य विकास योजना के तहत ऋण-सह-अनुदान पर डेयरी फार्मिंग योजनाओं के माध्यम से सशक्तिकरण करने एवं रोजगार के अवसर देना सुनिश्चित किया है । जिसके कारण इस क्षेत्र में रोजगार का अवसर बढ़ेगा । माननीय सभापति महोदय, हमारी केन्द्र की सरकार ने राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनाओं की स्वीकृति दी है जिसके अन्तर्गत मत्स्य हैचरी का निर्माण, तालाब का निर्माण आदि किया जाना है, जिसके कारण राज्य में मछली का उत्पादन बढ़ेगा तथा मछली के व्यवसाय से जुड़े किसानों एवं अन्य लोगों को काफी फायदा होगा । माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने वर्ष 2021-22 में भावी कार्यक्रम के तहत पशु एवं मत्स्य संसाधन का आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 में शामिल किया है, जिसके तहत आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार करना है तथा...

सभापति(श्री अवध विहारी चौधरी) : माननीय सदस्या, आपका समय समाप्त हुआ, कृपया स्थान ग्रहण करें । श्री मुरारी मोहन झा जी ।

श्रीमती कविता देवी : धन्यवाद ।

सभापति(श्री अवध विहारी चौधरी) : आपका समय दो मिनट है ।

श्री मुरारी मोहन झा : सभपति महोदय, मैं आपके प्रति एवं अपनी विधान सभा केवटी की जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिसके कारण मैं आज आप सबों के बीच बोलने के लिए सदन में उपस्थित हो पाया हूं । सभापति महोदय, जल संसाधन विभाग के बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और विपक्ष के कटौती प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । सभापति महोदय, विपक्ष के लोगों ने बहुत सारे सवालों को उठाया, मैं सिर्फ एक उदाहरण आप सबों के सामने देना चाहता हूं । कोसी परियोजना, जो दरभंगा ही नहीं पूरे मिथिलांचल के लिए एक बहुत बड़ी परियोजना थी । कोसी परियोजना का 1953-54 वर्ष में जिसकी नींव रखी गयी और उसका कार्य प्रारंभ 1973 में किया गया । मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या इस सरकार के पहले जितनी भी सरकारे आयीं

सभापति(श्री अवध विहारी चौधरी) : माननीय सदस्य, संक्षेप में अपनी बात को रखें क्योंकि सरकार का उत्तर होना है ।

श्री मुरारी मोहन झा : तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि अगर इनकी नीयत साफ रहती तो आज कोसी परियोजना की यह दुर्दशा नहीं होती । आज एन.डी.ए. सरकार के माध्यम से, जो सारी उपलब्धियां या सिंचाई के ऊपर जो कार्य किये जा रहे हैं, उस पर जितना भी कहा जाय कम होगा । अगर मुझे समय दिया जाय तो मैं कुछ बातों को, सरकार की जो उपलब्धि है, सरकार का जो प्रोग्राम है, वह मैं आपके समक्ष रखता हूं ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, वर्ष 2021 में बाढ़ के पूर्व की जाने वाली तैयारियों के अंतर्गत 270 अदद् बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं को 1,251.81 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण करने का कार्यक्रम है । महोदय, 116.36 करोड़ रुपये की लागत से सुपौल एवं मधुबनी जिलांतर्गत पश्चिमी कोसी तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, इस पर बिटुमिनस सड़कों का निर्माण एवं संरचनाओं का निर्माण, पुनर्स्थापन कार्य को तीव्र गति से कराया जा रहा है । महोदय, 110.65 करोड़ रुपये की लागत से सीतामढ़ी जिलांतर्गत रातो नदी के तट पर बाढ़ प्रबंधन योजना के तहत नो मेंस लैंड से निशा रोड तक तटबंध का निर्माण किया जा रहा है, जिसे मार्च, 2022 तक पूर्ण किया जायेगा ।

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ।

अध्यक्ष : अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अपना पक्ष रखें । कृपया पांच मिनट में समाप्त करें ।